सोशल वेव

हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष– 01 अंक– 01 अगस्त– 2023

सम्पादक
संध्या राय

प्रबन्ध सम्पादक
देवेंद्र वर्मा

mi सम्पादक
अमित राय

संवाददाता
vcjh'k xkLokeh ¼iVuk½
cjdr vyh ¼xkj[kiqj½
lR;Unz dqekj ¼y[kuÅ½
vfHk"kd jk; ¼egjktxat½

विधि सलाहकार
v'ouh JhokLro] ,MoksdsV
dfiy nso f=ikBh] ,MoksdsV

foKkiu çHkkjh
vfHk"kd xqIrk

ग्राफिक्स
nsoUnz flag

सम्पादकीय कार्यालय
665ch] xqxk Vkyk] utnhd tkudh
fcfYMx eVfj;y] ck'kkjriqj
oLV]xksj[kiqj] mÙkj çns'k 273003

TITLE CODE :- UPHIN51018

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक संध्या राय द्वारा फाइन ऑफसेट प्रिंटर्स मदरसा हुसैनिया बिल्डिंग बक्सीपुर से मुद्रित एवं न्यू कॉलोनी झरना टोला कूड़ाघाट से प्रकाशित।

नोट– पत्रिका से सम्बन्धित सभी वाद–विवाद गोरखपुर जिला न्यायालय के अन्तर्गत मान्य होगे ।

16
आसमानी रक्षा में बड़ी भारत की वायु-शक्ति

04
यूपी को मिलेगी आसमानी आफत से राहत

10
'कांग्रेस आएबे बारी है...

36
दिल्ली में बाढ़ से उपजे विकट हालात...

32
रश्मिका का क्यूट अंदाज

सम्पादक की कलम से...

दोस्ती और मजबूत होगी

संध्या राय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर फ्रांस में हैं। आज बैस्टील डे परेड प्रोग्राम में वह गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल होंगे। यह यात्रा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों का यह 25वां साल है। द्विपक्षीय रिश्तों के संदर्भ में यह बात याद की जा सकती है कि फ्रांस ने भारत को उस समय समर्थन दिया था, जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर प्रतिबंध लगाए जाने का फ्रांस ने विरोध किया था। इस पॉजिटिव पॉइंट से दोनों देशों के रक्षा संबंध आगे ही बढ़ते गए। फ्रांस भारतीय सेना को आधुनिक लड़ाकू जेट और पनडुब्बियों जैसे महत्वपूर्ण साजो-सामान की आपूर्ति करता रहा। 2018 से 2022 के बीच फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर बन गया। आज की तारीख में देश के कुल रक्षा आयात का 29 फीसदी फ्रांस से ही होता है। पीएम मोदी की मौजूदा यात्रा इस मायने में अहम मानी जा रही है कि इसमें 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स और तीन अतिरिक्त स्कॉर्पीन पनडुब्बियों की खरीद का समझौता हो सकता है। अगर यह हो जाता है तो भारत को सैन्य हथियारों के मामले में उस अनिश्चितता से उबरने में आसानी होगी, जो यूक्रेन युद्ध के चलते रूसी डिफेंस सप्लाई में आई बाधाओं के चलते पैदा हुई है। घरेलू खरीदारी की होड़ - मिक्सर ग्राइंडर, गीजर, वॉटर प्यूरीफायर और अन्य पर 70% तक की छूट। इसके अलावा भारत और फ्रांस के रिश्तों का एक और अहम पहलू यह है कि भू-राजनीति के हाल के दिनों में बदलते समीकरण भी इन दोनों देशों को करीब ला रहे हैं। कई वजहों से ट्रांस अटलांटिक अलायंस सिस्टम में फ्रांस कुछ अलग-थलग पड़ा दिख रहा है। उदाहरण के लिए, 2021 में बने ऑकस (ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका) का जिक्र किया जा सकता है, जिससे फ्रांस को बाहर रखा गया। फ्रांस इसका जवाब भारत जैसे देशों से अपनी करीबी बढ़ाने की कोशिशों के रूप में दे रहा है। यह स्थिति भारत के अनुकूल है, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसके साथ तालमेल बढ़ाना चाहता है। बढ़ाए भी क्यों ना। आखिर दोनों देश इस क्षेत्र में वर्चस्वादी चीन के खिलाफ हैं। लेकिन फिर भी दोनों देशों के रिश्तों का सबसे अहम पक्ष व्यापारिक गतिविधियों का ही है। इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा संभावनाएं भी हैं। हालांकि इस क्षेत्र में भी प्रगति हुई है लेकिन इसके बावजूद 2022-23 में दोनों देशों के बीच का व्यापार महज 12.56 अरब डॉलर का रहा। जानकारों के मुताबिक यह काफी कम है और थोड़े प्रयासों से भी इसमें अच्छा-खासा इजाफा हो सकता है। इसलिए दोनों पक्षों को अब भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जल्द से जल्द मुक्त व्यापार समझौता करने की दिशा में प्रयास तेज करने पर ध्यान देना चाहिए।

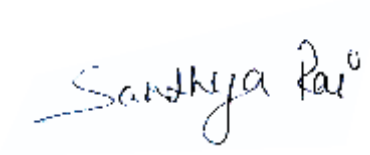

परमाणु हथियार विकसित करता उत्तर कोरिया

ब्यूरो

लगातार बैलिस्टिक मिसाइल के प्रक्षेपण करने वाले उत्तर कोरिया ने प्रतिबंधों को दरकिनार कर परमाणु हथियार को विकसित करना जारी रखा है, जिसको लेकर अमेरिका ने एक बार फिर चिंता जाहिर की है. रॉयटर्स ने संयुक्त राष्ट्र की एक अप्रकाशित रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह जानकारी दी है. रिपोर्ट के अनुसार,उत्तर कोरिया ने साइबर हैकिंग के जरिए करोड़ों पाउंड हासिल किए हैं, जिसका इस्तेमाल वह हथियारों पर कर रहा है. दरअसल, उत्तर कोरिया पर लगाए गए संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों पर निगरानी रखने वाले विशेषज्ञों के एक दल ने एक अप्रकाशित रिपोर्ट तैयार की है. इस रिपोर्ट में कहा कि उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियार विकसित करना और परमाणु विखंडनीय सामग्री का उत्पादन जारी रखा है.

संयुक्त राष्ट्र ने लगा रखे हैं कड़े प्रतिबन्ध

गौरतलब है कि उत्तर कोरिया ने साल 2006 में पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने उस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे. संयुक्त राष्ट्र ने प्योंग यांग की ओर से न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन रोकने के लिए देश के ज्यादातर निर्यात पर पाबंदी लगा दी और आयात को बहुत हद तक सीमित कर दिया था. हालांकि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार कर किम जोंग उन परमाणु हथियार को तेजी के साथ विकसित करने में लगा हुआ है.

किम ने हथियारों का उत्पादन बढ़ाने का दिया है निर्देश

गौरतलब है कि इससे पहले गुरुवार को उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने सेना के शीर्ष जनरल को हटा दिया था. साथ ही तानाशाह ने युद्ध की संभावना के लिए और अधिक तैयारी करने, हथियारों के उत्पादन को बढ़ावा देने और सैन्य अभ्यास के विस्तार का आह्वान किया. इस बात की जानकारी राज्य मीडिया के सीएनए ने दी थी.

ये गलत काम कर रहा है उत्तर कोरिया

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया में कोयले का अवैध निर्यात जारी है. इसके साथ ही कि उत्तर कोरिया ने प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए 14 नए जहाज भी हासिल किए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज और वित्तीय संस्थाओं पर साइबर अटैक से पैसे जुटाना नॉर्थ कोरिया के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत है. एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया पर 2 हजार से ज्यादा पाबंदियां लगी हुई हैं. इसके बावजूद भी ये देश लगातार अपनी सैन्य ताकत दिखाता रहा है. ■

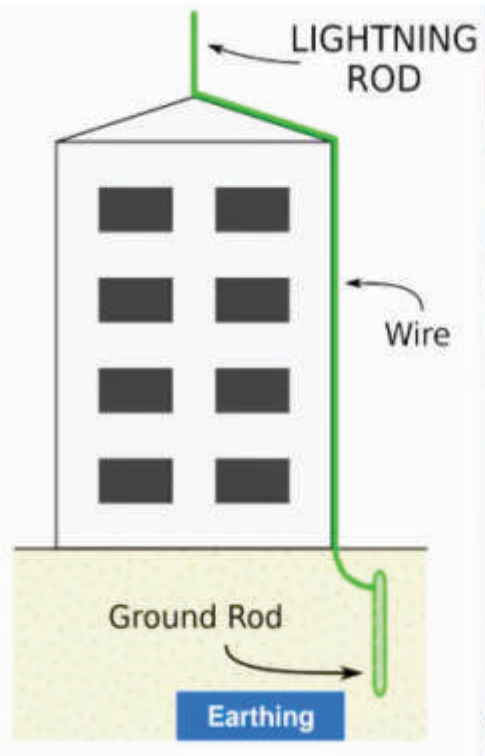

यूपी को मिलेगी

आसमानी आफत से राहत

आसमान से गिरने वाली बिजली को आकर्षित कर जमीन के अंदर भेज देगी लाइटनिंग रॉड। हर वर्ष बिजली गिरने से उत्तर प्रदेश में जाती हैं सैकड़ों जानें, 2023-24 में अब तक हुईं 174 मौतें। यूपी को मिलेगी आसमानी आफत से राहत लखनऊ। आपदा में प्रदेश के लोगों के लिए कवच की तरह काम करने वाली योगी सरकार ने अब प्रदेश में लोगों को आसमानी बिजली से होने वाले जनधन के नुकसान से बचाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

अंबरीश गोस्वामी (पटना)

यूपी में बिजली गिरने से होने वाले जनधन के नुकसान से बचाएगी योगी सरकार। ऊंची बिल्डिंगों पर लगाए जाएंगे लाइटनिंग अरेस्टर्स, आसमानी बिजली को करेंगे काबू। आसमान से गिरने वाली बिजली को आकर्षित कर जमीन के अंदर भेज देगी लाइटनिंग रॉड। हर वर्ष बिजली गिरने से उत्तर प्रदेश में जाती हैं सैकड़ों जानें, 2023-24 में अब तक हुईं 174 मौतें। यूपी को मिलेगी आसमानी आफत से राहत लखनऊ। आपदा में प्रदेश के लोगों के लिए कवच की तरह काम करने वाली योगी सरकार ने अब प्रदेश में लोगों को आसमानी बिजली से होने वाले जनधन के नुकसान से

बचाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। योगी सरकार प्रदेश में ऊंची बिल्डिंगों पर लाइटनिंग अरेस्टर्स या लाइटनिंग रॉड लगाने जा रही है, जो खराब मौसम में आसमानी बिजली को आकर्षित कर उसे सीधे जमीन के अंदर पहुंचा देगी। इससे न सिर्फ लोगों की जान बचाई जा सकेगी, बल्कि बिजली गिरने से होने वाले नुकसान को भी रोका जा सकेगा।

ऊंची बिल्डिंगों पर लगाई जाएगी लाइटनिंग रॉड

हाल ही में राहत आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के समक्ष लाइटनिंग अरेस्टर्स को लेकर प्रस्तुतिकरण में इसके लाभ के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि 2022-23 में उत्तर प्रदेश के 52 जिलों में बिजली गिरने से 301 लोगों की मृत्यु हो गई थी। वहीं 2023-24 में जुलाई तक 36 जिलों में 174 जानें बिजली गिरने की वजह से जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि पहले सोनभद्र जैसे जिलों में बिजली गिरने से काफी मौतें होती थीं, लेकिन अब गाजीपुर जैसे जिले इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ऐसे में हमने जिलों से रिपोर्ट मांगी है कि उनके यहां कहां पर यह लाइटनिंग रॉड लगाई जा सकती है। प्रस्ताव के अनुसार यह लाइटनिंग अरेस्टर या लाइटनिंग रॉड सबसे ऊंची बिल्डिंगों पर लगाई जा सकती है।

क्या है लाइटनिंग अरेस्टर्स या लाइटनिंग रॉड....?

एक लाइटनिंग रॉड या लाइटनिंग कंडक्टर एक धातु की छड़ है जो एक संरचना पर लगाई जाती है और इसका उद्देश्य संरचना को बिजली के हमले से बचाना है। यदि बिजली किसी संरचना से टकराती है तो यह सीधे रॉड पर हमला करेगी और संरचना से गुजरने के बजाय यह रॉड उसे एक तार के माध्यम से जमीन के अंदर ले जाएगी और संरचना को नुकसान होने से बचा लेगी। इसके माध्यम से बिजली को कहीं भी गिरने से रोका जा सकेगा, जिससे बड़ी संख्या में होने वाली जनधन की हानि को बचाया जा सकेगा।

कैसे काम करेंगे लाइटनिंग अरेस्टर्स....?

जब कहीं बिजली गिरती है तो यह एक बड़ा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाती है जो पास की प्रवाहकीय सामग्री जैसे विद्युत तारों और पाइपलाइन में उच्च वोल्टेज को प्रेरित कर सकती है। यह उच्च वोल्टेज संरचना को नुकसान पहुंचा सकता है और संभावित रूप से अंदर और आसपास उपस्थित लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। एक लाइटनिंग अरेस्टर या लाइटनिंग रॉड बिजली के प्रवाह को संरचना से दूर और जमीन में एक कम प्रतिरोध पथ प्रदान करती है। यह बिजली गिरने से होने वाले नुकसान को रोकने में मदद करता है और संरचना के अंदर या आसपास उपस्थित लोगों को बिजली के झटके से बचाने में भी मदद करती है। यूपी को मिलेगी आसमानी आफत से राहत ■

भारतीय संस्कृति का मूल

2018 में प्रधानमंत्री ने अबुधाबी में बनने वाले पहले हिन्दू मंदिर की आधारशिला रखी। उन्होंने 2019 में बहरीन की राजधानी अबुधाबी में श्रीकृष्ण श्रीनाथ के पुनर्निर्माण के लिए 4.2 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की। अमरनाथ और कैलाश मानसरोवर की यात्रा सुगम बनाई गई। 9 वर्ष में भारतीय संस्कृति के संवर्द्धन के लिए ऐतिहासिक कार्य हुए हैं।

हृदयनारायण दीक्षित

सत्य शिव और सुन्दर भारतीय संस्कृति के मूल तत्व हैं। भारतीय राष्ट्र का उद्भव सांस्कृतिक भाव भूमि में ही हुआ था। प्रकृति के प्रति आत्मीय भाव इस संस्कृति की विशेषता है। भारतीय संस्कृति उदात्त है। इस विशाल देश में यहाँ अनेक भाषाएं और अनेक बोलियां हैं। अनेक भाषाओं और बोलियों के बावजूद यहाँ सांस्कृतिक एकता है। सभ्यता राष्ट्र की देह है। संस्कृति प्राण है। यह कला, गीत, संगीत, स्थापत्य आदि अनेक रूपों में व्यक्त होती है। सबसे खास बात है भारतीय संस्कृति में विश्व एक परिवार है। 'वसुधैव कुटुंबकम' के सूत्र में समूचा विश्व परिवार जाना गया है। स्वाधीनता संग्राम सांस्कृतिक नवजागरण था। यूरोप के पुनर्जागरण से भिन्न था। ऋग्वेद में सभी दिशाओं से ज्ञान प्राप्ति की स्तुति है। काव्य साहित्य और स्थापत्य संस्कृति की अभिव्यक्ति रहे हैं। सभी भारतीय भाषाओं में राष्ट्र का सांस्कृतिक प्रवाह प्रकट होता रहा है।

संस्कृति का पोषण और संवर्द्धन प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। राष्ट्र राज्य का भी कर्तव्य है। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक संस्कृति और एक राष्ट्र की अवधारणा बिसरा दी गई। भारत की संस्कृति को कई संस्कृतियों का घालमेल बताया गया। इसे कम्पोजिट कल्चर कहा गया यहाँ अनेक बोलियां अनेक रीति रिवाज हैं। यहाँ विविधता है लेकिन विविधता के बावजूद सांस्कृतिक एकता भी है। यह बात डॉ० आंबेडकर ने 'पाकिस्तान आर पार्टीशन ऑफ इंडिया' में लिखी है। उन्होंने लिखा है कि यह बात सही है कि भारतवासी आपस में लड़ते झगड़ते हैं। लेकिन एक संस्कृति सबको जोड़े रखती है। भारतीय संस्कृति का मूल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संस्कृति संवर्द्धन पर उल्लेखनीय काम हुआ है। संस्कृति और धरोहरों का संरक्षण इन 9 वर्षों में एक विशेष एजेंडा रहा है। सांस्कृतिक धरोहरों की प्रतिष्ठा बढ़ी है।

संस्कृति के प्रतीक वाले स्थानों, खूबसूरत मंदिरों के पुनर्निर्माण का काम हुआ है। श्रीराम भारत के मन के महानायक हैं। सारी दुनिया में उनकी कीर्ति है। राजनीति का एक बड़ा भाग श्रीराम को इतिहास पुरुष नहीं मानता। श्रीराम काल्पनिक चरित्र बताए जाते रहे हैं। केंद्र की सरकार ने राम वन गमन नाम

की परियोजना शुरू की थी। यह मोदी जी की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना ने दुनिया के तमाम देशों को आकर्षित किया है। इस परियोजना में 9 राज्यों में फैले 15 केंद्रों का पुनर्निर्माण/निर्माण सम्मिलित है। श्रीराम इन्हीं 9 राज्यों से होकर निकले थे। ऐसे स्थलों को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करना लक्ष्य रहा है। केंद्र सरकार के साथ सम्बंधित 9 राज्यों की सरकारें इस योजना पर काम कर रही हैं। राम भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रतीक हैं। श्रीराम के नाम से भारत की विशेष पहचान है।

भारतीय संस्कृति का मूल

काशी को भारतीय संस्कृति की राजधानी कहा जाता है। अब वाराणसी आकर्षक नगर है। 2019 में प्रधानमंत्री की अपेक्षानुसार विश्वनाथ कॉरिडोर पर काम शुरू हुआ। मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार का काम भी साथ साथ चला। विश्वनाथ कॉरिडोर देश का दूसरा सबसे बड़ा कॉरिडोर है। 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। इस कॉरिडोर की चर्चा यत्र तत्र सर्वत्र होती है। मध्य प्रदेश का उज्जैन सांस्कृतिक महत्त्व का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ महाकाल के दर्शनार्थ लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते हैं। कालीदास की प्रतिष्ठित रचना 'मेघदूत' में महाकाल की प्रीतिकर उपस्थिति है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महाकाल कॉरिडोर का निर्माण हुआ। इसकी भव्यता और सुंदरता आकर्षक है। अक्टूबर 2022 को उज्जैन में प्रधानमंत्री जी ने ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के विस्तृत क्षेत्र 'महाकाल लोक' का लोकार्पण किया था। यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का तीर्थ है।

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्रीराम के जन्म स्थान में भव्य मंदिर की अभिलाषा सपना रही है। जन्म भूमि को लेकर अनेक आंदोलन हुए। 2019 में श्रीराम जन्म भूमि सम्बंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया। मोदी जी ने स्वयं अगस्त 2020 में इसकी आधारशिला रखी। अयोध्या पहले से ही भारतीय संस्कृति दर्शन और आस्तिकता का केंद्र रही है। केंद्र सरकार अयोध्या को उसकी प्रतिष्ठा के अनुसार एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल के रूप में विकसित कर रही है। यह काम इसी 9 वर्ष के दौरान शुरू हुआ। भव्य मंदिर का निर्माण जारी है। केंद्र और राज्य की सरकार बधाई की पात्र हैं। 2013 में केदारनाथ धाम के आस पास भीषण आपदा के कारण काफी क्षति हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के

नेतृत्व में इसकी भव्यता को फिर से संवारा गया। केदारनाथ मंदिर परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं किया था। केदारनाथ धाम का विकास जारी है। संस्कृति प्रेमियों और भारतीय दर्शन के निष्ठावान लोगों के मध्य शंकराचार्य का नाम श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। वे अद्भुत विद्वान थे। भारतीय चिंतन में 6 प्राचीन दर्शन हैं। शंकराचार्य जी ने वेदांत दर्शन को विश्वव्यापी बनाया था। पं० दीन दयाल उपाध्याय ने शंकराचार्य पर एक पुस्तक भी लिखी थी। 25 नवंबर 2021 को उत्तराखण्ड के केदारनाथ धाम में शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री जी ने किया था। मोदी सरकार ने उत्तराखण्ड के लिए चार धाम परियोजना शुरू की है।

यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जोड़ने वाली चार लेन सड़क का निर्माण जारी है। जम्मू कश्मीर के रघुनाथ मंदिर का भी पुनर्निर्माण किया गया। एक सरकारी अनुमान के अनुसार कश्मीर घाटी में लगभग 1842 आस्था केंद्र हैं। इनमें 952 मंदिर हैं। इनमें सिर्फ 212 में पूजा होती है। संविधान के अनुच्छेद 370 के हटने के बाद अनेक आस्था केंद्रों का पुनर्निर्माण हुआ है। लगभग 2300 वर्ष पुराने शारदा मंदिर की भी जीर्णोद्धार जारी है। कॉरिडोर का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। खीरभवानी मंदिर का भी सौंदर्यीकरण जारी है। फरवरी 2022 में हैदराबाद में ग्यारहवीं सदी के प्रख्यात संत व दार्शनिक रामानुजाचार्य के सम्मान में बनी 216 फिट ऊंची 'स्टेचू ऑफ इक्वैलिटी' का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। इस परिसर में 25 करोड़ की लागत से म्यूजिकल फाउंटेन का निर्माण कराया गया था। करतारपुर कॉरिडोर उपेक्षित रहा है। केंद्र सरकार ने यहाँ कॉरिडोर बनाए। उस स्थान तक पहुँचने के लिए मार्ग भी बनाया गया। गुरु गोविन्द सिंह के पुत्रों के शहादत दिवस को मोदी सरकार ने 'वीर बाल दिवस' घोषित किया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद मोदी जी के प्रयास से गुरु ग्रंथ साहिब की तीन प्रतियों की पवित्रता बनाए रखते हुए भारतीय वायु सेना के विमान से सुरक्षित रूप में भारत लाया गया।

9 वर्ष में दुनिया के दुसरे देशों में भी मंदिरों व सांस्कृतिक केंद्रों को भव्य बनाने का काम भी हुआ है। 2018 में प्रधानमंत्री ने अबुधाबी में बनने वाले पहले हिन्दू मंदिर की आधारशिला रखी। उन्होंने 2019 में बहरीन की राजधानी अबुधाबी में श्रीकृष्ण श्रीनाथ के पुनर्निर्माण के लिए 4.2 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की। अमरनाथ और कैलाश मानसरोवर की यात्रा सुगम बनाई गई। 9 वर्ष में भारतीय संस्कृति के संवर्द्धन के लिए ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। सेकुलरवाद के बहाने संस्कृति और हिन्दुत्व को सांप्रदायिक बताने की लत पृष्ठभूमि में है। विपक्षी दलों के नेता भी सांस्कृतिक प्रतीकों के प्रति निष्ठा व्यक्त कर रहे हैं। ■

देश में क्या है शर्म सभी है दोषी!

घटना चार मई की है, जब वीडियो में दिख रही 20 साल की युवती की आंखों के सामने उसके पिता और भाई की हत्या कर दी गई और पूरा परिवार उजाड़ दिया गया। दोनों महिलाओं को आतातायी भीड़ पुलिस के हाथों से खींच कर ले गई और उनको निर्वस्त्र किया, उनके साथ बलात्कार किया

अजीत द्विवेदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसके दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि वे मणिपुर के वीडियो को लेकर बहुत परेशान हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आगे बढ़ कर कहा है कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगा। लेकिन सवाल है कि दोषी कौन है? मणिपुर की इंफाल घाटी के मैती बहुल थौबल जिले की वह भीड़, जिसके सामने दो महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया या वो लोग जिन लोगों ने महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई या उनके साथ सामूहिक बलात्कार में शामिल हुए? क्या कांगपोक्पी जिले की पुलिस दोषी नहीं है, जिसने 18 मई को एफआईआर दर्ज किया और ठीक दो महीने बाद वीडियो वायरल होने तक कोई कार्रवाई नहीं की? क्या थौबल जिले की पुलिस के सिर यह अपराध नहीं आएगा, जिसकी आंखों के सामने कुकी-जोमी समुदाय के एक पूरे परिवार को उजाड़ दिया गया?

घटना चार मई की है, जब वीडियो में दिख रही 20 साल की युवती की आंखों के सामने उसके पिता और भाई की हत्या कर दी गई और पूरा परिवार उजाड़ दिया गया। दोनों महिलाओं को आतातायी भीड़ पुलिस के हाथों से खींच कर ले गई और उनको निर्वस्त्र किया, उनके साथ बलात्कार किया। तो क्या वह पुलिस इस अपराध में शामिल नहीं मानी जाएगी, जिसके सामने यह अत्याचार हुआ? फिर किन दोषियों को तलाश किया जा रहा है? चीफ जस्टिस को कार्रवाई करनी है तो हाई कोर्ट से ही क्यों नहीं शुरू करते, जिसके एक आदेश के बाद हिंसा की शुरुआत हुई थी? प्रधानमंत्री को कार्रवाई करनी है तो मुख्यमंत्री से शुरू क्यों नहीं करते, जिसके राज में स्त्रियों के साथ ऐसी बर्बर और अमानवीय घटना हो रही है और जिसकी वजह से पूरी दुनिया के सामने भारत शर्मसार हो रहा है?

दो महिलाओं के साथ अमानवीयता का वीडियो सामने आने के 12 घंटे के बाद राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि इस मामले में पहली गिरफ्तारी हो गई है। यह कितने शर्म की बात है! चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि घटना के 77 दिन के बाद राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है कि पहली गिरफ्तारी हुई है! क्या राज्य के मुख्यमंत्री को इस घटना की पहले से जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी नहीं थी तो राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक प्राधिकार के नाते उनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। वीडियो में दिख रहे दरिंदों को गिरफ्तार करने से पहले थौबल और कांगपोक्पी जिले की समूची पुलिस फोर्स पर कार्रवाई करने की जरूरत है,

जिन्होंने सब जानते बूझते कोई कार्रवाई नहीं की। जिस मैती बहुल थाना क्षेत्र की यह घटना है वहां के सभी पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जिस कुकी-जोमी बहुल थाना क्षेत्र में जीरो एफआईआर दर्ज हुई थी, उस थाना क्षेत्र के भी सभी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

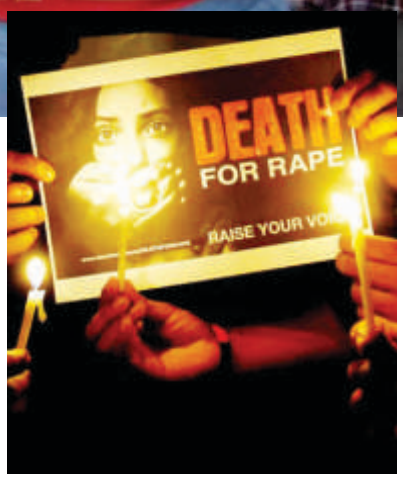

यह कोई सामान्य अपराध नहीं है, जिसमें दो-चार दोषियों की गिरफ्तारी हो और मामला रफा-दफा हो। यह समूचे सिस्टम के विफल होने की घटना है। अगर आप घटना की क्रोनोलॉजी सुनेंगे तब समझ में आएगा कि किस तरह से पूरे सिस्टम ने इस घटना को होने दिया और उसके बाद दबाए रखा। मणिपुर में तीन मई को कुकी और मैती समुदायों के बीच हिंसा की शुरुआत हुई थी। उसके अगले दिन चार मई को थौबल जिले के एक मैती बहुल इलाके में कुकी-जोमी समुदाय के एक परिवार के घर पर भीड़ ने हमला किया। परिवार के पांच लोग जान बचा कर भागे और पुलिस के पास पहुंचे। लेकिन भीड़ ने पुलिस के हाथों से उनको छीन लिया और दो पुरुष सदस्यों की मौके पर ही हत्या कर दी। उसके बाद दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया गया, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई गई और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। किसी तरह से महिलाएं वहां से भाग कर कुकी-जोमी बहुलता वाले इलाके में पहुंचीं और पुलिस के पास जाकर मुकदमा दर्ज कराया। चार मई की घटना पर अज्ञात लोगों के खिलाफ जीरो एफआईआर 18 मई को दर्ज की गई और मुकदमे की फाइल थौबल भेजी गई, जहां घटना घटित हुई थी। इस घटना का वीडियो बनाया गया

था और सैकड़ों लोग नंगी आंखों से इस घटना गवाह बने थे। फिर भी पूरे मणिपुर में मुर्दा शांति बनी रही। हैरानी की बात है कि शांति बहाली के प्रयास के लिए 29 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के दौरे पर गए। वे कुकी और मैती दोनों समुदायों को राहत शिविरों में गए।

क्या किसी ने उनको इस घटना के बारे में नहीं बताया? अगर नहीं बताया है तो अभी तक उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस, प्रशासन और खुफिया पुलिस के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है?

संपूर्ण मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना की जानकारी हजारों लोगों को थी। पुलिस के लोग घटना के बारे में जानते थे।

निश्चित रूप से राजनीतिक आकाओं को इसकी जानकारी होगी। लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर मणिपुर में पिछले ढाई महीने से चल रही हिंसा समाप्त क्यों नहीं हो रही है? हिंसा कैसे समाप्त होगी, जब इस तरह की वीभत्स घटना पर भी पुलिस और प्रशासन आंखें बंद किए रहेगा? इससे अपराधियों के हौसले बढ़े और दूसरी ओर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया की भावना भी प्रबल हुई। हिंसा भड़कने के दूसरे दिन हुई इस अमानवीय घटना की प्रतिक्रिया में न जाने कितनी हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया गया। अगर पुलिस ने उसी दिन कार्रवाई की होती और दोषियों को गिरफ्तार किया होता तो शायद हिंसा को रोकने में कामयाबी मिलती। लेकिन इस वीभत्स घटना को झूठे जातीय गर्व का चोला पहना दिया गया। इस्लामी देशों से लेकर अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देशों में भी जातीय, नस्ली हिंसा होती है लेकिन ऐसी वीभत्स घटना उन देशों से भी सुनने को नहीं मिलती हैं।

पहली नजर में यह पुलिस और प्रशासन की विफलता दिखती है लेकिन असल में यह एक समाज के नाते पूरे देश की और हर नागरिक की विफलता है। जिस समाज में महिलाओं के साथ इस तरह की घटना होती है वह समाज कहीं से सभ्य कहे जाने लायक नहीं है।

हम बलात्कार के दोषियों की रिहाई पर माला पहना कर उनका स्वागत करते हैं। हम स्त्रियों का यौन उत्पीड़न करने वाले को इसलिए बचाते हैं कि वह एक खास दल का सांसद है। फिर हम कैसे ऐसी घटनाओं से बच सकते हैं? हम कैसे एक समाज के रूप में विफल रहे हैं यह इस बात से भी पता चलता है कि सैकड़ों लोगों की जिस भीड़ के सामने इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया जा रहा था उस भीड़ में किसी की अंतरात्मा नहीं जागी। किसी ने आगे बढ़ कर उन स्त्रियों के शरीर पर एक कपड़ा नहीं डाला।

यह सही है कि दो निर्वस्त्र स्त्रियां वीडियो में दिख रही हैं लेकिन असल में नंगे वे सैकड़ों लोग थे, जो उस भीड़ का हिस्सा थे। वे जीते जागते लोग थे लेकिन उनकी आत्मा मर चुकी थी। सोचें, उस समय उन स्त्रियों का मन कैसे चीत्कार रहा होगा? क्या वे धरती फट जाने की कामना कर रही होंगी या पूरी सृष्टि के नष्ट हो जाने की प्रार्थना कर रही होंगी? घटनास्थल के हजारों मील दूर आज जिन लोगों का सचमुच कलेज फट रहा है वे भी उन महिलाओं की वास्तविक पीड़ा का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। यह पाप हम सब पर भारी है, सब इस पाप के भागीदार हैं, कोई क्षमा का हकदार नहीं है। ■

राहुल ने एनडीए और इंडिया का मुकाबला बताया

राहुल ने आगे कहा- भारत के विचार पर हमला हो रहा है, ये हमला बीजेपी कर रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है, अरबपतियों का फायदा हो रहा है, जो मोदी के करीबी हैं। राहुल ने प्रधानमंत्री को निशाना बनाते हुए कहा- नरेंद्र मोदी और इंडिया के बीच लड़ाई है। उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच की लड़ाई है।

बेंगलुरू। राहुल गांधी ने विपक्षी गठबंधन का नाम 'इंडिया' रखे जाने के बाद कहा कि यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की लड़ाई इंडिया से है। बेंगलुरू में हुई विपक्षी पार्टियों की बैठक के बाद साझा प्रेस कांफ्रेंस में राहुल ने कहा- आज देश की आवाज को दबाया जा रहा है। 'इंडिया' नाम इसलिए चुना गया, क्योंकि लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच है, मोदी और इंडिया के बीच में है। आपको पता है कि जब कोई इंडिया के खिलाफ खड़ा होता है तो जीत किसकी होगी।

राहुल ने आगे कहा- भारत के विचार पर हमला हो रहा है, ये हमला बीजेपी कर रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है, अरबपतियों का फायदा हो रहा है, जो मोदी के करीबी हैं। राहुल ने प्रधानमंत्री को निशाना बनाते हुए कहा- नरेंद्र मोदी और इंडिया के बीच लड़ाई है। उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच की लड़ाई है। हमने फैसला किया है कि हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे और एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा और हम जो करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे।

> केजरीवाल ने आगे कहा- देश में जिस तरह नफरत फैलाई जा रही है, उससे देश को बचाने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हिंदी फिल्म के डायलॉग के अंदाज में कहा- हम देश को बताने आए हैं कि मैं हूं ना।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साझा प्रेस कांफ्रेंस में कहा- देश में दलित, हिंदू, मुस्लिम हर किसी की जिंदगी खतरे में है। दिल्ली, बंगाल, मणिपुर हो, सरकार बेचना, सरकार खरीदना यही काम सरकार का है। हमारे गठबंधन का नाम 'इंडिया' है, बीजेपी क्या तुम इंडिया को चैलेंज करोगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा- नौ साल में केंद्र सरकार ने हर सेक्टर को बरबाद कर दिया है। इन्होंने एयरपोर्ट, जहाज, आसमान, धरती, पाताल सब बेच दिया। इनकी सरकार से किसान, व्यापारी हर वर्ग दुखी है।

केजरीवाल ने आगे कहा- देश में जिस तरह नफरत फैलाई जा रही है, उससे देश को बचाने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हिंदी फिल्म के डायलॉग के अंदाज में कहा- हम देश को बताने आए हैं कि मैं हूं ना। देश हमारा परिवार है। हम अपने परिवार को बचाने एकत्र हुए हैं। ■

‘कांग्रेस आएबे बारी है,
भाजपा जाएबे बारी है’

शुक्रवार को ग्वालियर में हुई प्रियंका गांधी की जनसभा में उठी हिलोरों के संकेत जिन्हें नहीं समझने हैं, ख़ुशी-ख़ुशी न समझें, लेकिन अब यह पूरी तरह साफ़ हो गया है कि साढ़े चार महीने बाद मध्यप्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में ‘कांग्रेस आएबे बारी है, भाजपा जाएबे बारी है‘। प्रियंका ने अपने भाषण के अंत में जब ग्वालियर-चंबल की स्थानीय बोली में ‘आएबे बारी-जाएबे बारी’ कहा तो लोगों में उन से निजी जुड़ाव का ऐसा उछाह नज़र आया, गोया लहरें आसमान की तरफ़ लपक रही हों।

बरकत अली

पूरी तरह साफ़ हो गया है कि साढ़े चार महीने बाद मध्यप्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में ‘कांग्रेस आएबे बारी है, भाजपा जाएबे बारी है‘। प्रियंका ने अपने भाषण के अंत में जब ग्वालियर–चंबल की स्थानीय बोली में ‘आएबे बारी–जाएबे बारी’ कहा तो लोगों में उन से निजी जुड़ाव का ऐसा उछाह नज़र आया, गोया लहरें आसमान की तरफ़ लपक रही हों। प्रियंका ने अपने भाषण की शुरुआत भी स्थानीय बोली में की। उन्होंने लोगों से कहा – ‘हमारी आप को राम–राम। … मैं पहले भी यहां आई हती पीतांबरा मैया के दरसन को। शुक्रवार को ग्वालियर में हुई प्रियंका गांधी की जनसभा में उठी हिलोरों के संकेत जिन्हें नहीं समझने हैं, ख़ुशी-ख़ुशी न समझें, लेकिन अब यह पूरी तरह साफ़ हो गया है कि साढ़े चार महीने बाद मध्यप्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में ‘कांग्रेस आएबे बारी है, भाजपा जाएबे बारी है‘। प्रियंका ने अपने भाषण के अंत में जब ग्वालियर-चंबल की स्थानीय बोली में ‘आएबे बारी-जाएबे बारी’ कहा तो लोगों में उन से निजी जुड़ाव का ऐसा उछाह नज़र आया, गोया लहरें आसमान की तरफ़ लपक रही हों।

प्रियंका ने अपने भाषण की शुरुआत भी स्थानीय बोली में की। उन्होंने लोगों से कहा – ‘हमारी आप

को राम-राम। ... मैं पहले भी यहां आई हती पीतांबरा मैया के दरसन को। ... इस क्षेत्र की वीरता की कहानियां मोए बचपन से पतो हैं। ...' प्रियंका के एक-एक लफ़्ज़ ने लोगों को दिली तरंगों से जोड़ने का ऐसा काम किया कि उन के उठाए मुद्दे अंतर्मन तक तैरने लगे। प्रियंका ने तमाम बुनियादी मसलों को एक नया आयाम दिया। उन्होंने पूछा कि क्या हमारी समूची राजनीति सिर्फ़ आरोप-प्रत्यारापों में ही फंसी रहेगी? क्या हम इस से आगे कोई बात नहीं कर सकते? क्या हम जनता के मुद्दों पर ठीक से चर्चा नहीं कर सकते?

प्रियंका की कही कुछ बातों पर ग़ौर कीजिए। ''स्वतंत्रता के हमारे आंदोलन को सत्याग्रह का नाम दिया गया था। राजनीति हमेशा से सत्य की लड़ाई है। हमारी परंपरा रही है कि हम नेताओं में सरलता, सादगी, सहजता और सच्चाई ढूंढते हैं। मगर आजकल एक दूसरे की बुराई का नाम राजनीति हो गया है। सब बस अवगुण गिनाते हैं। हम उनके गिनाते हैं, वो हम में अवगुण खोजते हैं। इसमें जनता के असली मुद्दे डूब जाते हैं।'' ''दूसरों की आलोचना करना बहुत आसान है। राजनीतिक सभ्यता को कायम रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है। दो दिन पहले विपक्ष की बड़ी बैठक हुई। लेकिन इस पर प्रधानमंत्री का बहुत आपत्तिजनक बयान आया। उन्होंने विपक्ष के सभी नेताओं और पार्टियों को सब धान ढाई पसेरी जैसा घोषित कर दिया। मणिपुर दो महीने से जल रहा है। महिलाओं के साथ भयावह अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन उस पर प्रधानमंत्री ने 77 दिनों तक कोई बयान नहीं दिया। एक भयावह वीडियो वायरल हुआ तो कल मजबूरी में उन्हें बोलना पड़ा। लेकिन उसमें भी उन्होंने राजनीति घोल दी।''

''अपने भाषण में मैं भी प्रधानमंत्री की आलोचना कर सकती हूं। शिवराज सिंह चौहान की सरकार के घोटालों की बात कर सकती हूं। आप के क्षेत्र के एक नेता की कैसे पूरी विचारधारा ही पलट गई, इस पर कह सकती हूं। लेकिन मैं ध्यान नहीं भटकाना चाहती। मैं आप के बुनियादी मुद्दों पर बात करने आई हूं। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। मगर महंगाई का राज़ समझिए। महंगाई के बहाने दरअसल आप की कमर तोड़ी जा रही है। सिर्फ़ रोज़मर्रा के खाने-पीने की चीज़ें ही महंगी नहीं हुई हैं। घर की मरम्मत महंगी हो गई है। बच्चों के स्कूल की फीस भरना मुश्किल हो गया है। बरसात में छाता खरीदना मुश्किल है। बहनों पर सब से बड़ा बोझ है। वे किस तरह गुज़ारा

कर रही हैं, कहा नहीं जा सकता। रसोई के लिए तेल खरीदना मुश्किल है। सिलेंडर में गैस भरवाना मुश्किल है। घर में कोई बीमार हो जाए तो घबराहट होती है कि दवाई कहां से लाऊं? ये परिस्थितियां जानबूझ कर बनाई गई हैं।''

''हर चुनाव में हर गांव-मुहल्ले में कोई नेता जाता है तो उस से कहिए कि जनता के मुद्दों पर बात करे। उस से पूछिए कि महंगाई क्यों है? बेरोज़गारी क्यों है? देश की पूरी संपत्ति एक दो लोगों को क्यों बेच दी? आप को रोजगार सरकारी कंपनियों से मिलता था। वे सब तो इन्होंने अपने दोस्तों को बेच दीं। आप को रोज़गार खेती से मिलता था, लेकिन किसानों को उपज की सही कीमत नहीं मिलती। आप को रोज़गार सेना से मिलता था, लेकिन फ़ौज में भर्ती को मखौल बना दिया। अग्निवीर योजना ले आए। मुझे कई लोगों ने बताया कि इस योजना में भर्ती हुए लोग अपनी ट्रेनिंग अधूरी छोड़-छोड़ कर लौट रहे हैं। उन्हें लगता है कि जब चार साल बाद वापस ही आना है तो इतनी कड़ी ट्रेनिंग क्यों करें? आप को रोज़गार छोटे कारोबार से मिलता था।

इन्होंने छोटे व्यवसाइयों को तबाह कर दिया। बड़े व्यवसाइयों को सारे धंधे सौंप दिए। जिस उद्योगपति को देश की सारी संपत्ति दे दी, वह 1600 करोड़ रुपए एक दिन में कमा रहा है और किसान 27 रुपए रोज़ नहीं कमा पा रहा। भौकाल की राजनीति है। देश का सच इसमें डूब रहा है।'' ''मध्यप्रदेश की सरकार के घोटालों की लंबी सूची मेरे पास है। ढाई हज़ार घोटाले हैं इनके। पटवारी के इम्तहान में घोटाला हो गया। महाकाल में भगवान की मूर्तियों तक को नहीं छोड़ा। इन से पूछिए कि 18 साल से सरकार है आप की, कितनी सरकारी नौकरियां दीं आप ने? अब चुनाव के वक्त लंबी-चौड़ी योजनाएं घोषित करने से क्या फायदा है? 18 साल से तो आपने कुछ किया नहीं। 1600 युवा बेरोज़गारी की वज़ह से आत्महत्या कर चुके हैं। आप को आत्मनिर्भर नहीं, सरकार पर निर्भर बनाने का काम हो रहा है। मैं ने बहुत-से लोगों से पूछा कि मुफ़्त का राशन चाहिए या नौकरी? ग़रीब से ग़रीब ने भी कहा कि राशन नहीं चाहिए, नौकरी दो ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हों।''

''जैसे इन्सान की जो नींव होती है, उसी तरह की उस की नीयत होती हे। वैसे ही सरकार का भी होता है। हमारी सरकार गिरा कर इन्होंने सरकार बनाई तो इसकी नींव ही गलत है। पैसे से खरीदी हुई सरकार है। तो वैसी ही नीयत है।

सिर्फ पैसा, पैसा, पैसा। 18 साल सत्ता में रहने से अहंकार होता ही होता है। आसपास के साथी अधिकारी भी सच्चाई नहीं बताते। 18 साल में लगने लगता है कि सत्ता तो हमेशा ही अपने पास रहेगी। जब चुनाव आएगा ध्यान भटका देंगे, दूसरी बातें करने लगेंगे, जनता के जज़्बात भड़का देंगे। जनता भूल जाएगी बुनियादी मसले और फिर वोट मिल जाएगा। सत्ता की वजह से अहंकार है, आलस्य है। सत्ता का स्वभाव है कि वह इंसान की असलियत उभार देती है। सत्ता नेक इंसान को दो वह भलाई के काम करेगा। गलत हाथों में दे दो तो इसी तरह की लूट मचेगी जो आज आपके प्रदेश में मच रही है।' आप के प्रदेश में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों पर भाजपा के नेता कैसे-कैसे अत्याचार कर रहे हैं। उन की एक-से-एक करतूतें सामने आई हैं। इसलिए आप को भविष्य के लिए बहुत बड़ा निर्णय करना है। ■

युग नेतृत्व के सक्षम आधार एवं नये धर्म के प्रवर्त्तक

स्वामी विवेकानन्द विश्वदीप थे, युग नेतृत्व के सक्षम आधार थे एवं नये धर्म के प्रवर्त्तक थे। उन्होंने भौतिकता के वातावरण में अध्यात्म की लौ जलाकर उसे तेजस्वी बनाने का उल्लेखनीय उपक्रम किया था। उन्होंने अध्यात्म साधना को परलोक से न जोड़कर वर्तमान जीवन से जोड़ने की बात कही।

ललित गर्ग

युग प्रवर्तक और युवाओं के प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानंदजी भारतीय संन्यास परंपरा और भारतीय मेधा के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। धर्म के साथ-साथ समाज में व्याप्त गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास छुआ-छूत और पलायनवाद पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा था। धर्म को वह केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं मानते थे। इनकी नजर में धर्म मनुष्य के समपूर्ण विकास का माध्यम है। धार्मिक संकीर्णता से वे ऊपर थे औऱ समस्त विश्व को अपना परिवार मानने के भारतीय दर्शन के प्रचारक थे। वे अनूठे संन्यासी थे, उनकी कीर्ति युग-युगां तक जीवंत रहेगी, क्योंकि उनका मानवहितकारी चिन्तन एवं कर्म कालजयी हैं, वे एक प्रकाश-स्तंभ हैं, भारतीय संस्कृति एवं भारतीयता के प्रखर प्रवक्ता, युगीन समस्याओं के समाधायक, अध्यात्म और विज्ञान के समन्वयक एवं आध्यात्मिक सोच के साथ पूरी दुनिया को वेदों और शास्त्रों का ज्ञान देने वाले एक महामनीषी युगपुरुष थे। जिन्होंने 4 जुलाई 1902 को महासमाधि धारण कर प्राण त्याग दिए थे। उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया, भारत को अध्यात्म के साथ विज्ञानमय बनाया, वे अध्यात्म एवं विज्ञान के समन्वयक थे। उन्होंने सारी वसुधा को अपना कुटुम्ब बनाने का सूत्र दिया, वसुधैव कुटुम्बकम का भारतीय मंत्र सारी दुनिया में पहुंचाया। जो अपने को प्रेम नहीं करता, वह किसी को प्रेम नहीं कर सकता। इसके लिये उन्होंने व्यापक प्रेम की वृत्ति और हृदय की विशालता को आवश्यक बताया।

स्वामी विवेकानन्द हिन्दुत्व की शुद्धि के लिये उठे थे और उनका प्रधान क्षेत्र धर्म था, उनकी दृष्टि में संन्यास एवं संतता संसार की चिन्ताओं से मुक्ति का मार्ग था। वे कहते थे कि चित्त शुद्धि के लिये अपने चारों ओर फैले हुए असंख्य मानवों की सेवा करो। आपस में ईर्ष्या-द्वेष रखने के बजाय, आपस में झगड़े, नफरत, घृणा असैर विवाद के बजाय, तुम परस्पर एक-दूसरे के हो जाओ, एक दूसरे की अर्चना करो। इन्हीं उन्नत विचारो एवं पुरुषार्थ से उन्होंने अपना एवं असंख्य मानवों का भाग्य रचा। उन्होंने सम्पूर्ण मानव समाज, हिन्दू समाज का और उन सभी को नया जीवन दर्शन दिया, जिनके भीतर थोड़ी भी आस्था एवं आत्मविश्वास था कि हमारा जीवन बदल सकता है। जो अपनी माटी एवं संस्कृति के प्रति समर्पित थे। वे साहसी एवं अभय बनने की प्रेरणा देते हुए कहते थे कि अभय हो! अपने अस्तित्व के कारक तत्व को समझो, उस पर विश्वास करो। भारत की चेतना उसकी संस्कृति

है। अभय होकर इस संस्कृति का प्रचार करो।' वे अच्छे दार्शनिक, अध्येता, विचारक, समाज-सुधारक एवं प्राचीन परम्परा के भाष्यकार थे। काल के भाल पर कुंकुम उकेरने वाले वे सिद्धपुरुष हैं। वे नैतिक मूल्यों के विकास एवं युवा चेतना के जागरण हेतु कटिबद्ध, मानवीय मूल्यों के पुनरुत्थान के सजग प्रहरी, अध्यात्म दर्शन और संस्कृति को जीवंतता देने वाली संजीवनी बंूटी, वेदान्त के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु हैं। वे अनावश्यक कर्मकांडों के विरुद्ध थे और हिन्दू उपासना को व्यर्थ के अनेक कृत्यों से मुक्त कराना चाहते थे। उन्होंने समाज की कपट वृत्ति, दंभ, क्रूरता, आडम्बर और अनाचार की भर्त्सना करने में संकोच नहीं किया।

स्वामी विवेकानन्द में सम्पूर्ण नारी समाज के लिये असीम उदारता एवं सम्मान का भाव था। उनका मानना था कि नारियां महाकाली की साकार प्रतिमाएं हैं। यदि तुमने उन्हें ऊपर नहीं उठाया, तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। नारी सम्मान में ही तुम्हारी उन्नति का मार्ग है। संसार की सभी जातियां नारियों का समुचित सम्मान करके ही महान हुई हैं। जो जाति नारी का सम्मान करना नहीं जानती, वह न तो अतीत में उन्नति कर सकी, न भविष्य में उन्नति कर सकेगी। इसी तरह उन्होंने समाज की युवाओं को सबल बनाने की प्रेरणा दी। उनकी हमेशा यही शिक्षा रही कि आज के युवक को शारीरिक प्रगति से ज्यादा आंतरिक प्रगति की जरूरत है। वे युवकों में जोश भरते हुए कहा करते थे कि उठो मेरे शेरांे! इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। वे एक बात और कहते थे कि जो तुम सोचते हो वह हो जाओगे। ऐसी ही कुछ प्रेरणाएं हैं जो आज भी युवकों को आन्दोेलित करती है, पथ दिखाती है और जीने का दर्शन प्रदत्त करती है। इन्हीं सुलझे एवं उच्च विचारों के कारण वे तत्कालीन युवापीढ़ी के आकर्षण का केन्द्र बने, इसमें कोई शक नहीं कि वे आज भी अधिकांश युवाओं के आदर्श हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नया भारत निर्मित करने की बात कर रहे हैं, उसका आधार स्वामी विवेकानन्द की शिक्षाएं एवं प्रेरणाएं ही हैं। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त संत एवं भारतीय पुनर्जागरण के पुरोधा पुरुष के रूप में माना जाता हैं। वे अध्यात्म की अतल गहराइयों में डुबकी लगाने वाले योग साधक थे तो व्यवहार में जीने वाले गुरु भी थे। वे प्रज्ञा के पारगामी थे तो विनम्रता की बेमिशाल नजीर भी थे। वे करुणा के सागर थे तो प्रखर समाज सुधारक भी थे। उनमें वक्तृता थी तो शालीनता भी। कृशता थी तो

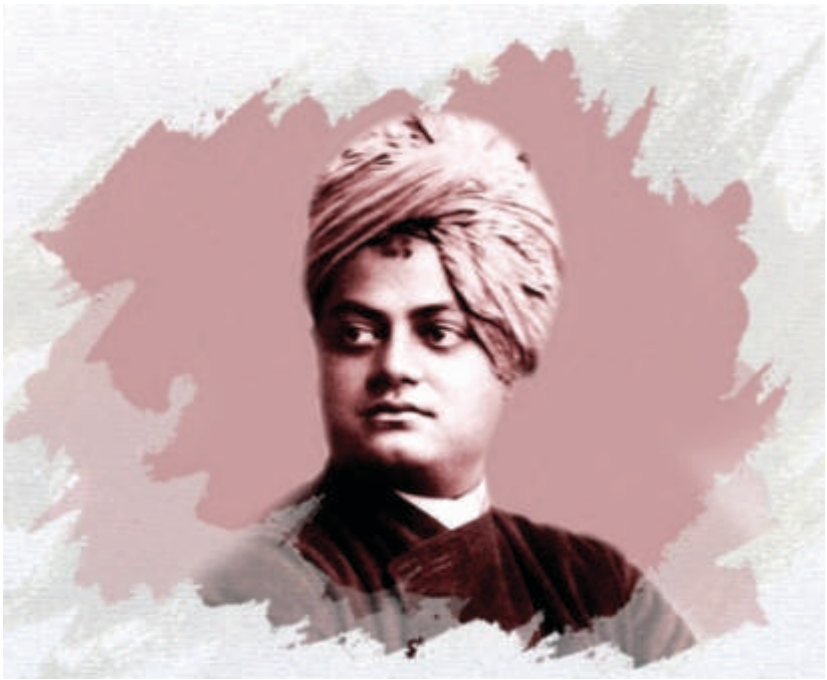

तेजस्विता भी। आभिजात्य मुस्कानों के निधान, अतीन्द्रिय चेतना के धनी, प्रकृति में निहित गूढ़ रहस्यों को अनावृत्त करने में सतत् संलग्न, समर्पण और पुरुषार्थ की मशाल, सादगी और सरलता से ओतप्रोत, स्वामी विवेकानन्द का समग्र जीवन स्वयं एक प्रयोगशाला था, एक मिशन था, भारतीय संस्कृति के अभ्युदय का अनुष्ठान था। स्वामी विवेकानन्द ने अमेरिका स्थित शिकागो में सन् 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदान्त दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में उनके प्रयासों एवं प्रस्तुति के कारण ही पहुँचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी जो आज भी भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिक मूल्यों को सुदृढ़ कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। कलकत्ता के एक कुलीन बंगाली परिवार में जन्मे विवेकानंद आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफी प्रभावित थे जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीव स्वयं परमात्मा का ही एक अवतार हैं। इसलिए मानव जाति की सेवा द्वारा परमात्मा की भी सेवा की जा सकती है। वे बड़े स्वप्नदृष्टा थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य-मनुष्य में कोई भेद न रहे। उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत से युवा संन्यासी चाहिये जो भारत के ग्रामों में फैलकर देशवासियों की सेवा में खप जायें। वे पुरोहितवाद, धार्मिक आडम्बरों, कठमुल्लापन और रूढ़ियों के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने धर्म को मनुष्य की सेवा के केन्द्र में रखकर ही आध्यात्मिक चिंतन किया था। उनका हिन्दू धर्म अटपटा, लिजलिजा और वायवीय नहीं था। स्वामी विवेकानन्द हर इंसान को शक्ति एवं समझसम्पन्न मानते थे, विश्व का हर कण शक्ति का अक्षय भंडार है और असीम स्रोत है। विश्व का दीप वह बनता है जो इस सत्य को अभिव्यक्ति देता है और दूसरों में अनुभूति की क्षमता जागृत करता है। हर युग हजारों संभावनाओं को लिए हुए हमारे सामने प्रस्तुत होता है। युग का नेतृत्व वह करता है जो उन संभावनाओं को वर्तमान का परिधान दे पाता है। वर्तमान युग संघर्षों का युग है। आज का प्रबुद्ध मनुष्य प्राचीन मूल्यों के प्रति आस्थावान होकर नए मूल्यों की स्थापना के लिए कृत-संकल्प है। युग का प्रधान वही हो सकता है जो इस संकल्प की पूर्ति में योग दे सकता है। स्वामी विवेकानन्द विश्वदीप थे, युग नेतृत्व के सक्षम आधार थे एवं नये धर्म के प्रवर्त्तक थे। उन्होंने भौतिकता के वातावरण में अध्यात्म की लौ जलाकर उसे तेजस्वी बनाने का उल्लेखनीय उपक्रम किया था। उन्होंने अध्यात्म साधना को परलोक से न जोड़कर वर्तमान जीवन से जोड़ने की बात कही। विलक्षण जीवन और विलक्षण कार्यों के माध्यम से उन्होने अध्यात्म को एक नई पहचान दी। स्वामी विवेकानन्द पुण्यतिथि पर उनको हार्दिक नमन! ■

आसमानी रक्षा में बड़ी

भारत की वायु-शक्ति

सशक्त और शक्तिशाली भारत के लिए देश की तीनों सेनाओं का आधुनिकतम शस्त्रों और युद्धक हवाई-जहाजों व हेलिकॉप्टरों से सुसज्जित होना आवश्यक है। इस दृष्टि से भारत ने लद्दाख में चीन से तनातनी के चलते रूस से 33 लड़ाकू विमानों की आपात खरीद का फैसला लिया था। रूस से 12 सुखोई-30 और 21 मिग-29 विमान खरीदने के सौदे हुए। इन सुपर सुखोई विमानों से 600 किमी तक मार करने वाली मिसाइलें दागी जा सकती हैं।

संध्या राय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिनी फ्रांस यात्रा सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। भारतीय नौसेना को उन्नत लड़ाकू विमानों 26 राफेल-एम (मैरी टाइम) और नौ सेना को तीन स्कार्पीन पनडुब्बी से सक्षम बनाने के नजरिए से खरीद के सौदे दोनों देशों की समीतियों ने तो तय कर लिए हैं,लेकिन खरीद की कीमत,तकनीक और व्यापारिक शर्तें अभी अंतिम रूप नहीं ले पाई हैं। इसलिए इस सौदे के पूर्ण होने में अभी वक्त लगेगा।हालांकि भारत की रक्षा क्रय परिषद विमानों और पनडुब्बियों की खरीद को मंजूरी दे चुकी है।दूसरी तरफ फ्रांसीसी एयर स्पेस कंपनी डसाल्ट एविएशन ने रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ती में कहा है कि फ्रांसीसी सरकार के साथ अंतर सरकारी समझौते के तहत भारतीय नौसेना के लिए संबंधित सहायक उपकरण, हथियार, सिम्युलेटर, स्पेयर पार्ट्स, चालक दल प्रशिक्षण के साथ राफेल समुद्री क्षेत्र में दुश्मन की टोह लेने वाले विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। भारत सरकार यह सौदा बड़ी सर्तकता और समझदारी से लेने के मूड में है,जिससे आमचुनाव में इसे विपक्ष को मुद्दा बनाकर उछालने की कोई गुंजाइश ही न रह जाए।क्योंकि फ्रांस से 2016 में जिन 36 राफेल विमानों का सौदा हुआ था, उस पर कांग्रेस व अन्य विपक्षों दलों ने विवाद खड़ा करने की बहुत कोशिश की थी।अतएव भारत ने राफेल-एम विमान का पहले सफल परीक्षण किया। जब यह विमान भारतीय नौसेना के परिचालन संबंधी आवश्यकताओं पर पूरी तरह से खरा उतरा तब इसकी खरीद को मंजूरी दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और फ्रांस इस साल रणनीतिक साझेदारी की रजत जयंती मना रहे हैं। इस साझेदारी के चलते दोनों देशों के बीच ढाई दशक में रक्षा, विज्ञान, प्रौधोगिकी के साथ संस्कृति के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा है। फ्रांस 2017 से 2021 के बीच भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा रक्षा संबंधी उपकरण आपूर्तिकर्ता देश रहा है। हालांकि भारत ने सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका से खरीदे हैं।सब कुल मिलाकर भारत आसमानी रक्षा क्षेत्र में अत्यंत शक्तिशाली देश बनता जा रहा है।

यह समुद्री लड़ाकू विमान नौसेना की जरूरतों के हिसाब से ही विकसित किया गया है। इसमें वे सभी आधुनिकतम समुद्री प्रणालियां संलग्न हैं, जिनसे समुद्र में दुश्मन और उसके समुद्री जल में भीतर चलने वाले उपकरणों का सुराग लगाया जा सकता है। इससे युद्धपोतों के अलावा पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए भी उच्च तकनीकि क्षमता के रडार भी लगे हुए हैं। इन विमानों को नौसेना के विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। यह विमान पुराने विमान मिग-29 का ठोस विकल्प साबित होगा। ऐसे विमानों की तलाश में भारत लंबे समय से था। क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन नाजायज वर्चस्व बढ़ाने में लगा है। फ्रांस भी चीन की इस बढ़ती आक्रामकता से चिंतित था। क्योंकि चीन हिंद महासागर में अंतरराष्ट्रीय नियमों का लगातार उल्लंघन कर रहा है। जबकि फ्रांस की मंशा इस सागर को खुले और समावेशी क्षेत्र के रूप में सुरक्षित बनाए रखना है। एक तरह से इन विमानों का सौदा चीन की मनमानी के विरुद्ध भारत और फ्रांस की साझा रणनीति का हिस्सा भी बनेगा। हालांकि इन विमानों की पहली खेप आने में तीन साल का इंतजार करना होगा, क्योंकि एक साल तक तो तकनीकी और लागत संबंधी औपचारिकताएं ही पूरी होंगी। बावजूद विशेषज्ञों का कहना है कि राफेल की यह खरीद इसलिए उचित है, क्योंकि भारतीय वायुसेना राफेल के रख-रखाव से संबंधित अधोसंरचना तैयार कर चुकी है। यही नौसेना के काम आ जाएगी। इससे धन की बचत होगी।

फ्रांस से कुल 26 राफेल-एम विमान खरीदे जाएंगे। इनकी प्रति विमान कीमत 5.5 अरब डालर अर्थात

45,000 करोड़ रुपए है। अभी कीमत को अंतिम रूप दिए जाने के लिए कीमत घटाने के और प्रयास किए जा रहे हैं।ये विमान उसी डा ॅसल्ट कंपनी से खरीदे गए हैं, जिससे 2016 में 36 राफेल विमान खरीदे गए थे। यह खरीद विवादित रहते हुए लोकसभा में भी चर्चित रही थी। जबकि अब इन विमानों की आपूर्ति के बाद भारत की रक्षा शक्ति बढ़ी है। राफेल-एम के सौदे में यह भी तय है कि भारत पेरिस में अपने दूतावास में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) का कार्यालय स्थापित करेगा। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग के दौरान यह काफी अहम् उपलब्धि है। यही नहीं भारत और फ्रांस अन्य देशों के फायदे के लिए अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों का सह-विकास और सह-उत्पादन करेगा। इसके लिए दोनों देश रक्षा औद्योगिक सहयोग पर एक रोडमैप अपनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं।

भारत सरकार पिछले चार साल से आईएनएस विक्रांत के लिए नए लड़ाकू विमान खरीदने की योजना पर विचार कर रही थी। दो साल पहले अमेरिकी बोइंग एफ-ए-18 सुपर हार्नेट और फ्रांसीसी राफेल-एम में से किसी एक को चुनने की प्रक्रिया पर काम शुरू हो गया था। भारतीय नौसेना ने 2022 में गोवा में दोनों विमानों के परीक्षण किए। इनकी खूबियों और खामियों को लेकर गंभीर अध्यन कर एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट के बाद भारतीय रक्षा विषेशज्ञों ने राफेल-एम को आईएनएस विक्रांत की जरूरतों के अनुकूल पाया, जबकि बोइंग एफ-ए 18 को लेकर विषेशज्ञों के बीच एक राय नहीं बन पाई। इसलिए राफेल एम खरीदने का रास्ता खुल गया। यह विमान 15.27 मीटर लंबा और 10.80 मीटर चैड़ा है। इसकी ऊंचाई 5.34 मीटर है। इसका कुल वजन 10,600 किलोग्राम है। यह 1912 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेगा। 3700 किमी के व्यास में यह 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। चूंकि यह विमान पोत से उड़ान भरते हैं, इसलिए इनमें ऊंची और लंबी छलांग लगाने की क्षमता के लिए ताकतवर इंजन होना चाहिए। क्योंकि पोत पर विमान को छोटे मार्ग से उछाल मारकर उड़ान भरनी होती है। ये सब खूबियां इस विमान में हैं।

याद रहे देश की रक्षा ताकत बढ़ाने की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में फ्रांस यात्रा के दौरान फ्रांसीसी कंपनी डसा ॅल्ट एविएशन से ही 36 राफेल जंगी जहाजों का सौदा किया था। यह

सौदा अर्से से अधर में लटका था। इस सौदे को अंजाम तक पहुंचाने की पहल ने वायु सैनिकों को संजीवनी देकर उनका आत्मबल मजबूत करने का काम किया है। फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे हुई बातचीत के बाद यह सौदा अंतिम रुप ले पाया था। इस लिहाज से इस सा ॅदे के दो फायदे देखने में आए थे। एक ये युद्धक विमान जल्दी से जल्दी हमारी वायुसेना के जहाजी बेड़े में शामिल हो गए। दूसरे, इस खरीद में कहीं भी दलाली की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी, क्योंकि सौदे को दोनों राष्ट्र प्रमुखों ने सीधे संवाद के जरिए अंतिम रूप दिया था। जबकि पूर्व प्रधानमंत्री डा ॅ.मनमोहन सिंह और रक्षा मंत्री एके एंटनी की साख ईमानदार जरूर थी, लेकिन ऐसी ईमानदारी का क्या मतलब, जो जरूरी रक्षा हथियारों को खरीदने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए? जबकि ईमानदारी तो व्यक्ति को साहसी बनाने का काम करती है। हालांकि रक्षा उपकरणों की खरीदी से अनेक किंतु-परंतु जुड़े होते हैं, सो इस खरीद से भी जुड़ गए थे, लेकिन कोई कमी सामने नहीं आई। भारतीय सेना के लिए लड़ाकू विमानों की खरीद इसलिए जरूरी थी, क्योंकि हमारे लड़ाकू बेड़े में शामिल ज्यादातर विमान पुराने होने के कारण जर्जर हालत में हैं। अनेक विमानों की उड़ान अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद उनका इस्तेमाल किया जाता रहा है। पिछले दो दशक से कोई नया विमान नहीं खरीदा गया है। इन कारणों के चलते आए दिन जेटों के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इन दुर्घटनाओं में वायु सैनिकों के बिना लड़े ही शहीद होने का सिलसिला बना हुआ है। अब राफेल विमानों की थोक खरीद के बाद दुर्घटनाओं में तो विराम लगेगा ही, हमारे सैनिक बिना लड़े शहीद भी नहीं होंगे।

नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही रक्षा सौदों में गंभीर रुचि ली जा रही है। अमेरिका से 165 अरब रुपए के लड़ाकू हेलिकॉप्टर एवं अन्य रक्षा उपकरण खरीदने का बड़ा सौदा हुआ था। अमेरिका विमानन कंपनी बोइंग से 22 अपाचे हमलावर हेलिकॉप्टर और 15 शिनूंक भारी उद्वहन हेलिकॉप्टर खरीदा जाना देश की सुरक्षा के लिए जरूरी था। फ्रांस से 36 राफेल खरीदे गए। एक राफेल विमान की अनुमानित कीमत करीब 58,000 करोड़ रुपए है। पिछले करीब 20 साल से देश ने लड़ाकू विमानों का कोई सौदा नहीं किया था। इस वजह से वायुसेना में लड़ाकू विमानों की लगातार कमी होती जा रही थी। नतीजतन देश की हवाई सुरक्षा खतरे में पड़ी थी। हालात इतने गंभीर होते जा रहे थे कि उपलब्ध विमानों के बेड़ों की संख्या घटकर 32 के करीब पहुंच गई थी। लड़ाकू विमान व हथियारों के ये सौदे इसलिए अहम् है, क्योंकि हमारे पड़ोसी दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान में लड़ाकू विमान लगातार बढ़ रहे हैं। इन दोनों देशों की वायु-शक्ति की तुलना में हमारे पास कम से कम 756 लड़ाकू विमान होने चाहिए। सेना में विमान, हथियार और रक्षा उपकरणों की कमी की चिंता संसद की रक्षा संबंधी स्थाई संसदीय समिति और नियंत्रक एवं

महानिरीक्षक की रिपोर्टें भी जताती रही हैं। संसदीय समिति ने तो यहां तक कहा था कि लड़ाकू जहाजी बेड़ों की संख्या में इतनी कमी पहले कभी नहीं देखी गई। यह स्थिति सैनिकों का मनोबल गिराने वाली है। गड़बड़ घोटालो में उलझी रही डॉ मनमोहन सिंह सरकार अपने 10 साल के कार्यकाल में विमान खरीदने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाई थी। दरअसल, सौदों में भ्रष्टाचार के चलते इटली की फिनमैकेनिका और उसकी सहयोगी कंपनी अगस्तावेस्तलैंड हेलिकॉप्टरों की खरीदी में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष शशींद्रपाल त्यागी पर सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज होने के बाद संप्रग सरकार ने सैन्य सामग्री खरीदने के सिलसिले में घुटने टेक दिए थे।

अपाचे का सौदा हाइब्रिड है। इस हेलिकॉप्टर में हथियार,रडार और इलेक्ट्रोनिक युद्ध उपकरण लगे हुए हैं। पिछले एक दशक के दौरान अमेरिकी कंपनियों ने तकरीबन 10 अरब डॉलर मूल्य के रक्षा सौदे भारत से किए हैं। इनमें पी-81 नौवहन टोही विमान,सी-130,जे सुपर,हरक्यूलियस और सी-17 ग्लोबमास्टर-3 जैसे विमानों की खरीद शामिल हैं। अपाचे एएच-64 लॉन्गबो हेलिकॉप्टर आधुनिक होने के साथ बहुलक्षीय युद्धक विमान है। यह हर मौसम और रात में भी युद्ध अभियानों में सक्रिय रहने की क्षमता रखता है। इसकी प्रमुख खूबी है कि यह एक मिनट से कम समय में 128 लक्ष्यों को चिन्हित कर सकता है और 16 लक्ष्यों पर निशाना साधता हुआ बच निकल सकने की विलक्षणता रखता है। दुश्मन के रडार पर इसका अक्श दिखाई नहीं देता। इसके संवेदी यंत्र आधुनिक हैं और इसकी मिसाइलें, जो दृश्य दिखाई दे रहा है, उससे भी आगे तक प्रहार करने की क्षमता रखती हैं। इसकी अधिकतम गति 315 किमी प्रति घंटा है। जबकि समुद्र में यही गति 240 किमी प्रति घंटा रह जाती है। यह 55 सैनिक और 12,700 किलोग्राम वजन ढो सकता है। कारगिल जैसे ऊंचाई वाली चोटियों पर भी यह हेलिकॉप्टर पहुंच सकता है। गालवन की चोटियों पर भी यह आसानी से पहुंच जाएगा। अपाचे और शिनूंक हेलिकॉप्टरों का उपयोग अफगानिस्तान और ईराक जैसे सैन्य अभियानों में बेमिशाल रहा है।

बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद वायुसेना ने तमिलनाडू के तेंजावुर में सुखोई-30 एमकेआई के बेड़े को तैनात किया है। इस बेड़े में सुखोई विमानों को 2.5 टन की हवा से हवा में मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस किया हुआ है। ये मिसाइलें 300 किलोमीटर की दूरी तक अचूक निशाना साधने में सक्षम हैं। इस एक बेड़े में 18 लड़ाकू विमान होते हैं। पिछले कुछ सालों में वायुसेना ने युद्धक क्षमताओं को बढ़ाते हुए हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों व अन्य घातक हथियारों की क्षमता बढ़ाई है। इनमें बेहतर मारक क्षमता वाले स्पाइस 2000 बम और स्ट्रम अटाका नाम की एंटी-गाइडेड मिसाइलें शामिल हैं।

बहरहाल लड़ाकू विमानों एवं हथियारों की आश्चर्यजनक कमी से जूझ रही वायुसेना को ये विमान एवं हथियार आक्सीजन साबित हो रहे हैं। तमाम शंका-कुशंकाओं के बावजूद ये विमान खरीदना इसलिए जरूरी थे, क्योंकि हमारे लड़ाकू बेड़े में शामिल ज्यादातर विमान पुराने होने के कारण जर्जर हालत में आ गए थे। अनेक विमानों की उड़ान अवधि समाप्त होने को है और पिछले 20 साल से कोई नया विमान नहीं खरीदा गया है। सोवियत रूस से 1960 और 70 के दशक में खरीदे गए मिग-21 और मिग-27 विमानों के तीन बेड़ों को भी सेवामुक्त कर दिया गया है। उम्र पूरी हो जाने के कारण ज्यादातर विमान उड़ान भरने की अवधि के करीब होने के कारण आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे थे। इन दुर्घटनाओं के चलते बहादुर वायु-सैनिकों को बिना लड़े ही शहीद होना पड़ रहा था।

1978 में जब जागुआर विमानों का बेड़ा ब्रिटेन से खरीदा गया था, तब ब्रिटेन ने हमारी लाचारी का फायदा उठाते हुए हमें ऐसे जंगी जागुआर बेचे थे, जिनका प्रयोग ब्रिटिश वायुसेना पहले से ही कर रही थी। राफेल भी फ्रांस द्वारा प्रयोग में लाए गए विमान हैं। दरअसल, हरेक सरकार परावलंबन के चलते ऐसी ही लाचारियों के बीच रक्षा सौदे करने को मजबूर होती है। लिहाजा जब तक हम विमान निर्माण के क्षेत्र में स्वावलंबी नहीं होंगे, लाचारी के समझौतों की मजबूरी झेलते रहेंगे। यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि हम चीन की तुलना में कम सैन्य क्षमता वाले देश हैं। हालांकि हमारी सैनिक संख्या चीन से ज्यादा हैं। ग्लोबल फायर पॉवर डॉट कॉम के मुताबिक भारत के पास लगभग 34,62,500 सैनिक हैं, जबकि चीन के पास 26,93,300 हैं।

हकीकत तो यह है कि मोदी सरकार को अब लाचारियों से भरी विमान खरीदों के स्थायी समाधान तलाशने की जरूरत है, जो पारदर्शी नीतियों का पालन करने वाली हो। साथ ही एचएएल एवं डीआरडीओ जैसी संस्थाओं का आधुनीकिकरण और स्वेदेशीकरण किया जाना नितांत जरूरी है। फिलहाल हमारे यहां हल्के युद्धक विमान और आधुनिकतम हल्के किस्म के हेलीकॉप्टर बनाए जा रहे हैं। टाटा कंपनी सी-130 मॉडल के विमानों के पुर्जे भारत में बनाकर दूसरे देशों में निर्यात कर रही है। जब ऐसा संभव है तो हम अपने ही देश के लिए शक्तिशाली युद्धक विमानों का निर्माण क्यों नहीं कर सकते ? एचएएल भारतीय कंपनियों को उपकरण व पुर्जे बनाने का लाइंसेंस देकर इस दिशा में उल्लेखनीय पहल कर सकती है। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी तकनीक से ध्रुव नाम का हेलिकॉप्टर बनाया जा रहा है। ध्रुव हल्का बहुउद्देश्यीय हेलिकॉप्टर है। इसे थल, जल और नभ तीनों सेनाएं उपयोग में ले रही हैं। जरूरत पड़ने पर यह लड़ाकू विमान के साथ मालवाहक और एंबुलैंस के रूप में भी काम आता है। इसकी विशेषता है कि यह हवा में डॉल्फिन की तरह गोता लगा सकता है, यू आकार में मुड़ सकता है और खड़े रूप में भी तीर की भांति उड़ान भर सकता है। बावजूद यह मिसाइल दागने और बड़ी मात्रा में हथियार ले जाने में समर्थ नहीं है। हालांकि रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश की मात्रा शत-प्रतिशत कर देने से ये संभावनाएं बढ़ने की उम्मीद है। यदि भविष्य में ऐसा होता है तो हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' यानी स्वदेशीकरण का जो स्वप्न है, उसके साकार होने की उम्मीद भी बढ़ जाएगी। यह सब मोदी है तो मुमकिन है। ■

सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में

भारत बनेगा ग्लोबल सेंटर !

यह हम सभी को गौरवान्वित करता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के निवेशकों को आमंत्रित करते हुए यह बात कही है कि, 'भारत में 2026 तक 80 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर की खपत होने लगेगी और 2030 तक ये आंकड़ा 110 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा।

सत्येन्द्र कुमार

भारत सेमीकंडक्टर(अर्धचालक) प्रोडक्शन (उत्पादन) में अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। यह वाकई अत्यंत ही काबिलेतारिफ है कि भारत सरकार हमारे देश को सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वप्रथम हमें यह जानने की जरूरत है कि आखिर सेमीकंडक्टर होते क्या हैं और उनका उपयोग क्या है ? तो इस संबंध में जानकारी देना चाहूंगा कि अर्धचालक (सेमीकंडक्टर) या एडवांस्ड माइक्रोचिप उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों (जैसे ताँबा) से कम किन्तु अचालकों (जैसे कांच) से अधिक होती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड आदि कुछ सेमीकंडक्टर पदार्थों के उदाहरण हैं। जानकारी मिलती है कि आधुनिक युग में प्रयुक्त तरह-तरह की युक्तियों (डिवाइसेज) के मूल में ये अर्धचालक या सेमीकंडक्टर पदार्थ ही हैं। जानकारी देना चाहूंगा कि सेमीकंडक्टर पदार्थों की सहायता से ही पहले डायोड बनाया गया और फिर ट्रांजिस्टर। वास्तव में सच तो यह है कि इन्हीं के कारण एलेक्ट्रॉनिक युग की असली शुरूआत हुई। विद्युत और एलेक्ट्रानिकी में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि अर्धचालक प्रकाश एवं अन्य विद्युत संकेतों को आवर्धित (एम्प्लिफाई) करने वाली युक्तियाँ बनाने, विद्युत संकेतों से नियंत्रित स्विच बनाने, तथा ऊर्जा परिवर्तक के रूप में काम करते हैं और आज के इस आधुनिक युग में सेमीकंडक्टरों का बहुत बड़ा उपयोग व महत्व है। पाठकों को शायद ही इस बात की जानकारी होगी कि मिसाइल गाइडेंस प्रणाली, विमानन और नौसैनिक नौवहन के साथ कई अन्य रक्षा प्रणालियों के लिए सेमीकंडक्टर बहुत जरूरी हैं। ऐसे में सेमीकंडक्टर चिप की कमी दूर करने के लिए, भारत को अपने इस उद्योग को बढ़ावा देना आवश्यक हो गया है और जानकारी देना चाहूंगा कि इसी क्रम में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में इंडिया सेमिकॉन सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने प्रौद्योगिकी फर्मों को भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग लगाने के लिए 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता देने की बात भी कही है। वास्तव में आज का युग सूचना क्रांति का युग है, कम्प्यूटर, एंड्रॉयड मोबाइल, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है और इस युग में सेमीकंडक्टरों का जितना महत्व है उतना शायद

किसी अन्य चीजों का नहीं। अब तक जापान, चीन, ताइवान, दक्षिणी कोरिया और अमेरिका जैसे देश ही सेमीकंडक्टर उत्पादन में आगे रहे हैं और भारत सेमीकंडक्टरों के लिए विदेशों पर ही निर्भर रहा है लेकिन अब भारत इस क्षेत्र में नये प्रतिमान स्थापित करने के लिए निरंतर आगे बढ़ता दिख रहा है। यहां यह उल्लेखनीय है कि 80 प्रतिशत सेमीकंडक्टरों का निर्माण एशिया में ही होता है और दुनिया के सर्वाधिक उन्नत किस्म के सेमीकंडक्टर के 92 प्रतिशत का निर्माण ताइवान में होता है। ताइवान इस क्षेत्र में अग्रणी है। एक जानकारी के अनुसार सेमीकंडक्टर का मार्केट दुनियाभर में करीब 500 अरब डॉलर का है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट के अनुसार, सेमीकंडक्टर दुनिया में चौथा सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला प्रोडक्ट है। इसमें दुनिया के 120 देश भागीदार हैं। सेमीकंडक्टर से ज्यादा ट्रेड सिर्फ क्रूड ऑयल, मोटर व्हीकल व उनके कल-पुर्जों और खाने वाले तेल का ही होता है। जानकारी मिलती है कि कोरोना से पहले साल 2019 में टोटल ग्लोबल सेमीकंडक्टर ट्रेड की वैल्यू 1.7 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गई थी। जानकारी देना चाहूंगा कि सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही जटिल एवं प्रौद्योगिकी-गहन क्षेत्र है जिसमें भारी पूंजी निवेश, उच्च जोखिम, लंबी अवधि तथा पेबैक अवधि तथा प्रौद्योगिकी में तीव्र बदलाव शामिल हैं, जिसके लिये महत्त्वपूर्ण और निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है। भारत में फेब्रिकेशन क्षमताओं की भी विदेशों की तुलना में अब तक कमी थी, सेमीकंडक्टर निर्माण का सेट अप भी काफी महंगा पड़ता है। यहां तक कि एक जानकारी के अनुसार एक सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई (या फैब) की लागत अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर भी स्थापित करने में इसकी लागत अरबों डॉलर की हो सकती है और यह तकनीक के संदर्भ में एक या दो पीढ़ी पीछे की भी हो सकती है। जानकारी देना चाहूंगा कि वर्ष 2021 में भारत ने देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये लगभग 10 बिलियन डॉलर की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना की घोषणा की थी और वर्तमान में भारत की तरफ से दुनियाभर की चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है। भारत की ओर से इस आमंत्रण पर चीन खिसियानी बिल्ली की तरह खम्भा नोंच रहा है क्यों कि चीन को भारत का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आगे बढ़ना रास नहीं आ

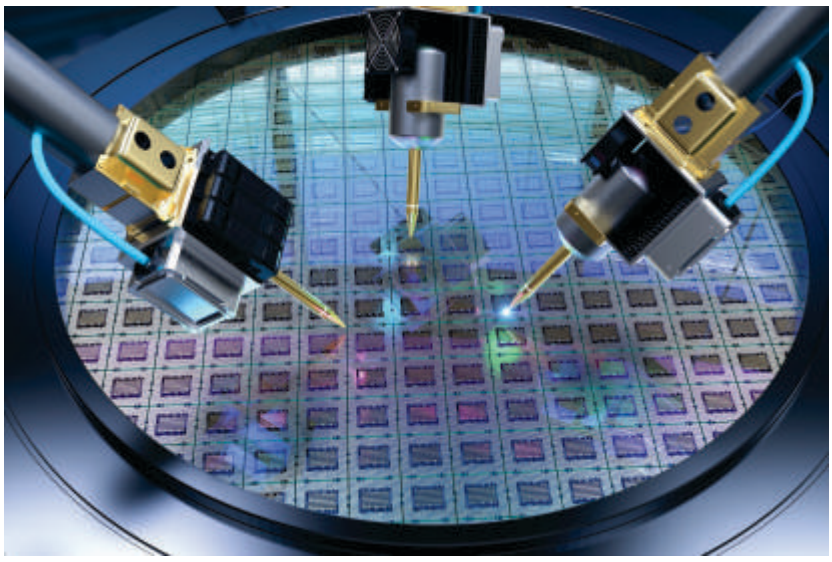

रहा है। यह ठीक है कि चीन स्वयं सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में किंग की भूमिका में रहा है लेकिन भारत अब चीन समेत दुनिया के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में महारथ हासिल देशों को टक्कर देने जा रहा है। चीन ने भारत के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में प्रगति को लेकर भारत को 'विदेशी निवेश की कब्रगाह' तक करार दे दिया है।

चीन की मीडिया का कहना है कि अमेरिका के समर्थन के बावजूद भारत का रास्ता कठिन है। बहरहाल, चीन जो भी सोचे और समझें लेकिन वर्ष 2014 में राष्ट्रों की वैश्विक लीग में 10 वें स्थान पर रहने वाला भारत आज दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत आज हरेक क्षेत्र में लगातार प्रगति के नये सोपानों को छू रहा है। आज कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र को सेमीकंडक्टर की जरूरत है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है, क्यों कि आज हम कम्प्यूटर, संचार क्रांति व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हसीन युग में सांस ले रहे हैं जो कि मानवता को बहुत सी सहूलियतें प्रदान करने जा रहा है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान तीन प्रमुख सेमीकंडक्टर समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पहला माइक्रोन प्रौद्योगिकी, दूसरा अनुप्रयुक्त सामग्री, सबसे जटिल उपकरण जो सेमीकंडक्टर निर्माण में प्रयोग किया जाता है, उसका निर्माण भी भारत में करने से सबंधित है। तीसरा लैम रिसर्च से हुआ समझौता है, यह अपने सेमीवर्स प्लेटफॉर्म पर 60,000 इंजीनियरों को प्रशिक्षित करेगा। आज लैपटॉप से लेकर फिटनेस बैंड तक और महीन कंप्यूटिंग मशीन से लेकर मिसाइल तक में आज एक ही चीज धड़क रही है और यह सेमीकंडक्टर या माइक्रोचिप ही है। आज डेटा का युग है और डेटा बिना सबकुछ अधूरा ही है। जिसके पास आज डेटा वह दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और डेटा, कम्प्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड्रॉयड स्मार्टफोन (मोबाइल) कहीं न कहीं सेमीकंडक्टर पर ही आधारित हैं। जानकारी देना चाहूंगा कि कोविड महामारी के उफान के दिनों में जब इन सेमीकंडक्टर्स या माइक्रोचिप्स की सप्लाई धीमी हो गई थी तो दुनिया भर के लगभग सैकड़ों बड़े उद्योगों में हड़कंप मच गया था। यहां तक कि बहुत सी दिग्गज और बड़ी कंपनियों को भी अरबों डॉलरों का नुकसान उठाना पड़ा था। पाठकों को जानकारी प्राप्त करके हैरानी होगी कि चीन, अमेरिका और ताइवान जैसे माइक्रोचिप्स के सबसे बड़े निर्यातक देशों की कंपनियों को भी प्रोडक्शन रोकना पड़ा था। बहरहाल, भारत के लिए सेमीकंडक्टर अब एक हसीन पल है। यह हम सभी को गौरवान्वित करता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के निवेशकों को आमंत्रित करते हुए यह बात कही है कि, 'भारत में 2026 तक 80 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर की खपत होने लगेगी और 2030 तक ये आंकड़ा 110 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा।' उम्मीद करते हैं जल्द ही भारत भी चीन, अमेरिका, ताइवान, जापान और दक्षिणी कोरिया जैसे देशों,जो कि सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में बहुत आगे हैं,को पछाड़कर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सिरमौर बन जाएगा। ■

डेढ़ अरब की आबादी के लिये घातक है

साम्प्रदायिक हिंसा

कुछ सम्पदाएं ऐसी हैं कि अगर आप आश्वस्त हो जाएं कि वे आपके हाथ में हैं तो आपके हाथ रिक्त हो जाते हैं। इन्हें स्वयँ जीकर ही जीवित रखा जाता है। आज हमारे पास ऐसा एक भी राजनेता नहीं है जो नफरत, घृणा एवं द्वेष की साम्प्रदायिक स्थिति से राष्ट्र को बाहर निकाल सके, राष्ट्रीय चरित्र को जीवित रखने का भरोसा दिला सके। डेढ़ अरब की यह निराशा कितनी घातक हो सकती है।

ललित गर्ग

हरियाणा के जिला नूंह में धार्मिक शोभायात्रा पर पथराव के बाद भड़की साम्प्रदायिक हिंसा ने जो विकराल रूप लिया है वह भयावह एवं चिन्ताजनक तो है ही, यह सवाल भी छोड़ता है कि कानून-व्यवस्था को चुनौती देते हुए साम्प्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की ऐसी घटनाएं आखिर थम क्यों नहीं रही हैं? क्यों प्रशासन अराजक तत्वों के आगे इतना बेबस हो जाता है? क्यों चुनावों से पहले ही ऐसी अराजक एवं साम्प्रदायिक शक्तियों सक्रिय होकर देश की शांति एवं सौहार्द की स्थितियों को तार-तार करने लगती है? क्यों नफरती, घृणा एवं द्वेष के भड़काव भाषणों पर नियंत्रण का बांध नहीं बांधा जाता? क्यों बार-बार सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की हिंसा, आगजनी एवं साम्प्रदायिकता के खिलाफ गुहार लगानी पड़ती है? अगर हर बार हिंसा रोकने के लिये गुहार न्यायपालिका से करनी पडे, तो विधायिका एवं कार्यपालिका की सार्थकता कितनी रह जाती है? इन प्रश्नों के अलावा मूल प्रश्न है कि आखिर नूंह की घटना ने समूचे हरियाणा को हिंसा की आग में क्यों और किस तरह झोंक दिया और इसका जिम्मेदार कौन है?

नूंह की साम्प्रदायिक हिंसा एक षडयंत्र एवं सुनियोजित साजिश थी। इस हिंसा के मामले में आवश्यकता इसकी भी है कि उसके पीछे के कारणों की तह तक जाया जाए, क्योंकि इतनी भीषण हिंसा बिना किसी सुनियोजित साजिश के नहीं हो सकती। नूंह में भयावह साम्प्रदायिक उन्माद एवं हिंसा में जलाभिषेक यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के साथ पुलिस को निशाना बनाया गया, बड़े पैमाने पर आगजनी, गोलीबारी और लूटपाट हुई, तभी इसके प्रतिक्रियास्वरूप अन्य इलाकों में हिंसा हुई, जिससे बचा जा सकता था।

एक वर्ग विशेष में इस तरह की हिंसा को जानबूझकर दावानल बनने दिया जा रहा है, जिसका विस्फोट कभी हरियाणा तो कभी दिल्ली, कभी राजस्थान तो कभी अन्य प्रांतों में होता रहता है, जिसमें राजनीतिक दलों के अलावा, बुद्धिजीवी वर्ग एवं मीडिया की सक्रिय भूमिका है। इन पर नियंत्रण के लिये जरूरत सख्त कदम उठाने की हैं। नूंह हो या दिल्ली, किसी भी दोषी को बचाने की जरूरत नहीं हैं। हम आज एक अराजक एवं उन्मादी तत्व को बचायेंगे तो कल ऐसे दस पैदा हो जायेंगे। इसके लिये उत्तरप्रदेश का योगी मॉडल ही कारगर है।

साम्प्रदायिक तनाव एवं हिंसा की हर घटना के बाद एहतियाती उपाय भी खूब होते हैं लेकिन इस अहम सवाल का जवाब हमेशा बहुत पीछे छूट जाता है कि आखिर दंगों की ऐसी आग, आए दिन देश के अलग-अलग हिस्सों को क्यों झुलसाने लगी है? दूसरा सवाल यह भी कि ऐसी साम्प्रदायिक हिंसा के लिए दोषी किसे ठहराया जाए? नूंह के मामले को भी बारीकी से समझा जाए तो लगता है कि प्रशासन

नियंत्रण से बाहर होती हमारी व्यवस्था हमारे लोक जीवन को अस्त-व्यस्त कर रही है। प्रमुख रुप से गलती राजनेताओं और सरकार की है। कहीं, क्या कोई अनुशासन या नियंत्रण है? निरंतर साम्प्रदायिकता का दावानल फटता रहता हैं। कोई जिम्मेदारी नहीं लेता- कोई दंड नहीं पाता। राजनीति संकीर्ण एवं सम्प्रदायीकरण, इसी का चरम बिन्दु है। अपराधी केवल वे ही नहीं जिनके दिलों में सम्प्रदायिक संकीर्णता का जहर घुला है।

और पुलिस ने इस धार्मिक जुलूस को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही बयानबाजी को गंभीरता से नहीं लिया। संवेदनशील इलाकों में धार्मिक जुलूस की अनुमति देने से पहले जो पड़ताल की जानी चाहिए वह आखिर क्यों नहीं की गई? नूंह ही नहीं, बल्कि ऐसे सभी मामलों में सरकार में बैठे लोगों को इन सवालों के जवाब गंभीरता से तलाशने होंगे। एक बात और, ऐसे दंगों के बाद राजनेताओं और धर्म के ठेकेदारों के बयानों पर भी नजर रखनी होगी जो बेवजह समुदायों को उकसाने का काम करते हैं। हेट-स्पीच का बढ़ता प्रचलन ऐसी साम्प्रदायिक हिंसा को भड़काने का मूल कारण है। न जाने कितने नफरती भाषण ऐसे रहे, जिनमें किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। नूंह की हिंसा के मामले में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भड़काऊ भाषण दोनों पक्षों की ओर से दिए गए। स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यह कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि नफरती तत्वों को जरूरी सबक मिले। कई बार तो घोर आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आवरण पहना दिया जाता है। भड़काऊ भाषणों पर कार्रवाई के मामले में दोहरे मानदंड समस्या को बढ़ाने वाले ही सिद्ध हो रहे हैं। यह जो साबित करने की कोशिश हो रही है कि ऐसे भाषण केवल किसी एक विशेष समूह या विचारधारा से जुड़े लोग ही दे रहे हैं, वह एक शरारती एजेंडा है और उसे बेनकाब करने की आवश्यकता है। क्योंकि हिंसा करने वाले दोषी लोगों से ध्यान हटाने यह एक जरिया है।

देश में दंगों की आग कब और कहां भड़क जाए, यह कोई नहीं जानता। खास तौर पर धार्मिक जुलूस निकालने को लेकर छिड़ा कोई विवाद जब साम्प्रदायिक तनाव में बदल जाए तो फिर हिंसा की आग बेकाबू होते देर नहीं लगती। यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऐसी घटनाओं में हर

बार जान-माल का भारी नुकसान सरकारी दस्तावेज में सिर्फ आंकड़ा बन कर ही रह जाता है। नूंह के दंगों की आग ने जो विकराल रूप लिया, उसके चलते वहां कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई है। हरियाणा के छह जिलों में निषेधाज्ञा लगाने के साथ-साथ हरियाणा से सटे राजस्थान के भरतपुर में भी अलर्ट जारी करना पड़ा है। नूंह दंगों की आंच गुरुग्राम तक जा पहुंची है जहां एक धार्मिक स्थल को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया जिसमें एक जने की मौत हो गई, मौतें तो और भी हुई है।

सब जानते हैं कि वोट बैंक पर कब्जा करने की राजनीति भी दंगों के पीछे छिपे कारणों में से एक रहती है। धर्म के नाम पर उन्माद से फायदा उठाने की चाह रखने वाले लोग ऐसे दंगों की आंच में भी अपनी सियासी रोटियां सेंकने से बाज नहीं आते हैं। दंगे भड़कने और हालात तनावपूर्ण हो जाने के बाद दंगों को दुर्भाग्यपूर्ण बताने और शांति की अपील करने मात्र से कुछ नहीं होने वाला। सरकारों को सख्त कदम उठाने ही होंगे।

नियंत्रण से बाहर होती हमारी व्यवस्था हमारे लोक जीवन को अस्त-व्यस्त कर रही है। प्रमुख रूप से गलती राजनेताओं और सरकार की है। कहीं, क्या कोई अनुशासन या नियंत्रण है? निरंतर साम्प्रदायिकता का दावानल फटता रहता हैं। कोई जिम्मेदारी नहीं लेता- कोई दंड नहीं पाता। राजनीति संकीर्ण एवं सम्प्रदायीकरण, इसी का चरम बिन्दु है। अपराधी केवल वे ही नहीं जिनके दिलों में सम्प्रदायिक संकीर्णता का जहर घुला है। वे भी हैं जो लोकतंत्र को तोड़ रहे हैं या जिनके दिमागों में अपराध एवं उन्माद भावना है। उन्मादी एवं अपराधी नियंत्रण से बाहर हो गये हैं। साम्प्रदायिक सोच वाले व्यक्ति नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। और सामान्य आदमी के लिए जीवन नियंत्रण से बाहर हो गया है। अगर हम राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचारें तो हमं स्वीकारना होगा कि बहुत-सी बात हमारे नियंत्रण से बाहर होती जा रही हैं।

वर्तमान दौर की सत्ता लालसा की चिंगारी इतनी प्रस्फुटित हो चुकी है कि सत्ता के रसोस्वादन के लिए जनता और व्यवस्था को पंगु बनाने की राजनीति चल रही है। प्रश्न है कि राजनीतिक पार्टियां एवं राजनेता सत्ता के नशे में डूबकर इतने आक्रामक एवं गैरजिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? जैसे-जैसे आम चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं साम्प्रदायिकता की जहर उगलने वाली स्थितियां ज्यादा प्रभावी होती

देश में दंगों की आग कब और कहां भड़क जाए, यह कोई नहीं जानता। खास तौर पर धार्मिक जुलूस निकालने को लेकर छिड़ा कोई विवाद जब साम्प्रदायिक तनाव में बदल जाए तो फिर हिंसा की आग बेकाबू होते देर नहीं लगती। यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऐसी घटनाओं में हर बार जान-माल का भारी नुकसान सरकारी दस्तावेज में सिर्फ आंकड़ा बन कर ही रह जाता है। नूंह के दंगों की आग ने जो विकराल रूप लिया, उसके चलते वहां कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई है।

जा रही है। बिना मेहंदी लगे ही हाथ पीले करने की फिराक में सभी राजनीतिक दल जुट चुके हैं। सवाल यह खड़ा होता है कि इस अनैतिक राजनीति का हम कब तक साथ देते रहेंगे? इस पर अंकुश लगाने का पहला दायित्व तो हम जनता पर ही है।

सत्ता से जुड़े एवं राजनीतिक स्वार्थ की रोटियां सेंकने वाले साम्प्रदायिक सौहार्द एवं सद्भावना कायम करने में नकारा साबित हो रहे हैं इसलिये सुप्रीम कोर्ट की ओर से समाज को ऐसा कोई संदेश जाना चाहिए कि घृणा का जबाव घृणा, नफरत का जवाब नफरत और हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकती।

सभी को यह समझना ही होगा कि शांति और सद्भाव का वातावरण ही उनके और देश के हित में है। यदि समाज अपने नैतिक और नागरिक दायित्वों को लेकर नहीं चेतता तो फिर चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाने से भी बात बनने वाली नहीं। इतने बड़े देश में यह काम आसानी से संभव भी नहीं। राष्ट्रीय जीवन में सौहार्द, शांति एवं सद्भावना ऐसी सम्पदाएं हैं कि अगर उन्हें रोज नहीं संभाला जाए या रोज नया नहीं किया जाए तो वे खो जाती हैं। कुछ सम्पदाएं ऐसी हैं जो अगर पुरानी हो जाएं तो सड़ जाती हैं।

कुछ सम्पदाएं ऐसी हैं कि अगर आप आश्वस्त हो जाएं कि वे आपके हाथ में हैं तो आपके हाथ रिक्त हो जाते हैं। इन्हें स्वयँ जीकर ही जीवित रखा जाता है। आज हमारे पास ऐसा एक भी राजनेता नहीं है जो नफरत, घृणा एवं द्वेष की साम्प्रदायिक स्थिति से राष्ट्र को बाहर निकाल सके, राष्ट्रीय चरित्र को जीवित रखने का भरोसा दिला सके। डेढ़ अरब की यह निराशा कितनी घातक हो सकती है। ■

चुनावी मुकाबले में 'इंडिया'

अब अगर सिर्फ नाम बनाने के लिए इन शब्दों को नहीं वापस नहीं गया है, तो कहा जा सकता है कि उसी विकास नजरिए के जरिए 'इंडिया' एनडीए का मुकाबला करने की रणनीति बनाएगा। इस बात की झलक नव-गठित गठबंधन के साझा बयान में भी मिली।

बयान में कहा गया है कि 'इंडिया' रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख भूमिका को बहाल करेगा। यह एक बड़ा वादा है। इसे पूरा करने की नए गठबंधन के पास क्या रणनीति है, इसका संकेत संभवतः उसके साझा न्यूनतम कार्यक्रम में मिलेगा।

छब्बीस विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम कुछ इस ढंग से रखा, जिससे उसका शॉर्ट फॉर्म 'इंडिया' बने। इस तरह उन्होंने भारत के मतदाताओं के मन को छूने की कोशिश की है।

इस प्रयास में उन्होंने दो शब्द अपने नाम के फुल फॉर्म में जोड़े- डेवलपमेंटल और इन्क्लूसिव। इस तरह इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस (इंडिया) बना। अगर थोड़ा पीछे मुड़ कर देखा जाए, तो जब यूपीए का शासन था, तब इन्क्लूसिव डेवलपमेंट शब्द काफी प्रचलित था। यूपीए ने अपनी विकास दृष्टि को इसी शब्द से व्यक्त किया था, जो वैसे नव-उदारवादी नीतियों के साथ सारी दुनिया में पहुंचा था।

अर्थ यह है कि जो विकास हो, वह समावेशी हो। यानी उसके लाभ सभी तबकों तक पहुंचें। इसके लिए यूपीए के जमाने में एक सोशल एजेंडा अपनाया गया था, जिसे कार्यरूप देने के लिए सोनिया गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनाई गई थी।

अब अगर सिर्फ नाम बनाने के लिए इन शब्दों को नहीं वापस नहीं गया है, तो कहा जा सकता है कि उसी विकास नजरिए के जरिए 'इंडिया' एनडीए का मुकाबला करने की रणनीति बनाएगा।

इस बात की झलक नव-गठित गठबंधन के साझा बयान में भी मिली। इसमें मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए कहा गया है कि 'इंडिया' रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख भूमिका को बहाल करेगा। यह एक बड़ा वादा है। इसे पूरा करने की नए गठबंधन के पास क्या रणनीति है, इसका संकेत संभवतः जब यह अपना साझा न्यूनतम कार्यक्रम जारी करेगा, तब मिलेगा। फिलहाल, यह अपेक्षा जरूर जताई जा सकती है कि गठबंधन आज के तकाजे को देखते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य को भी रणनीतिक क्षेत्र का हिस्सा माने। इन दो पैमानों पर देश में प्रयाप्त प्रगति ना होने का असर यह है कि देश आर्थिक विकास की अपनी संभावनाओं को भी हासिल नहीं कर पा रहा है।

इन क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के हाथ में छोड़ देने से आम जन का जीवन महंगा हुआ है, जिसका खराब असर उनकी कुल खुशहाली पर पड़ा है। इस सूरत को बदलने का संकल्प अगर नया गठबंधन ले, तो वह शायद इंडिया का दिल भी जीत पाएगा। ■

महिलाओं एवं बच्चियों के

लापता होने की त्रासदी

बात मणिपुर की दो महिलाओं या बंगाल के मालदा में दो महिलाओं को नग्न करने या समूचे देश में महिलाओं के लापता होने से अधिक चिन्ता की बात यह है कि इन शर्मसार करने एवं झकझोर देने वाली घटनाओं पर भी राजनीतिक दल राजनीति करने से बाज नहीं आते। इन अति संवेदनशील मुद्दों पर राजनीतिक लाभ की रोटियां सेंकना दुर्भाग्यपूर्ण है।

ललित गर्ग

मणिपुर में 19 जुलाई को दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाने का वीडियो वायरल हुआ था, उस घटना ने देश-विदेश के सभ्य समाजों को झकझोर दिया है। अब ऐसी ही एक घटना पश्चिम बंगाल के मालदा में सामने आई है। यहां भीड़ ने दो महिलाओं की पिटाई की, फिर उन्हें अर्धनग्न कर दिया गया। यह घटना मालदा के बामनगोला पुलिस स्टेशन के पाकुआ हाट इलाके में हुई। दोनों पीड़ित महिलाएं आदिवासी हैं। जब उनकी पिटाई हो रही थी और कपड़े उतारे जा रहे थे तो पुलिस वहां मूकदर्शक बनी खड़ी हुई थी। बात केवल आदिवासी महिलाओं की नहीं है, बात केवल महिलाओं पर हो रहे अपराधों, यौन-उत्पीड़न, बलात्कार, हिंसा की भी नहीं है, बल्कि अधिक विचलित करने वाली बात महिलाओं एवं बच्चियों के लापता होने की है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की ओर से संकलित आंकड़ों के अनुसार 2019 से 2021 के बीच यानी मात्र तीन वर्षों में देश भर में 13 लाख से अधिक लड़कियां और महिलाएं लापता हुई हैं। इन लापता होने वाली लड़कियों और महिलाओं में दलित, आदिवासी जनजाति की संख्या ज्यादा है। एक आदिवासी महिला के देश के राष्ट्रपति होने के बावजूद महिलाओं पर बढ़ते अपराध एवं लापता होने की घटनाएं अधिक चिन्ता का सबब है।

विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर एवं दुनिया की तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था का दावा करने वाले देश की महिलाएं मध्ययुग से भी ज्यादा सामंती सोच, असंवेदना, असुरक्षा, हिंसा, वीभत्स अपराधों और हवस की शिकार बन रही

हैं। आज जब देश में हर मुद्दे पर बहस छिड़ जाना आम बात हो गई है, दर्जनों टी.वी. चैनल एक से ही सवाल पर घंटों बहस करते हैं, आम चुनाव की चौखट पर खड़े देश के राजनीति दल ज्वलंत मुद्दों के नाम पर सरकार को घेरने की तलाश में रहते हैं तो इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के लापता होने एवं यौन-उत्पीड़न के सवाल पर बहस क्यों नहीं छेड़ी जाती? बहस इस बात पर भी होनी चाहिए कि दिल्ली के निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानूनों को कठोर किया गया लेकिन कानून बन जाने के बाद भी स्थितियां क्यों नहीं सुधरी हैं?

चिन्ता का कारण है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में कोई विशेष कमी आती नहीं दिख रही है। वे पहले की ही तरह यौन अपराधियों का शिकार बन रही हैं, लापता हो रही है। छेड़छाड, बलात्कार, अपहरण, लापता होने और दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।

बड़ा प्रश्न है कि तमाम कानून एवं सुरक्षा व्यवस्थाएं होने के बावजूद आखिर इतनी बड़ी संख्या में लड़कियां और महिलाए कहां गायब हो रही हैं? यह वह प्रश्न है, जिसका उत्तर नीति-नियंताओं के साथ ही समाज को भी देना होगा, क्योंकि यह ऐसा मामला नहीं, जिसके लिए केवल सरकारों को कठघरे में खड़ा कर कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाए। गायब होती लड़कियों और महिलाओं के मामले में समाज भी उत्तरदायी है। स्वयं को देश का भाग्य निर्माता मानने वाले राजनीतिक दल भी इसके दोषी है। इन सबको अपने अंदर झांकना होगा और स्वयं से यह प्रश्न करना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि देश के कई हिस्सों में अभी बालक-बालिकाओं का अनुपात संतुलित नहीं हुआ है, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या का सिलसिला कायम है। यह सिलसिला कानूनों को कठोर करने के बाद भी कायम है।

गायब होने वाली लड़कियों में अच्छी-खासी संख्या नाबालिग लड़कियों की भी है। इसका मतलब है कि नारी सुरक्षा का मामला बहुत ही गंभीर है। यह मानने का कोई कारण नहीं कि 2021 के बाद स्थितियों में सुधार आया होगा, क्योंकि लड़कियों और महिलाओं के लापता होने या उनका अपहरण किए जाने अथवा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के समाचार आए दिन आते ही रहते हैं। महिलाओं के प्रति यह संवेदनहीनता एवं बर्बरता कब तक चलती रहेगी? भारत विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी कई हिस्सों में महिलाओं को लेकर गलत धारणा है कि महिलाएं या बेटियां शोषण एवं उत्पीड़न के लिये ही हैं। एक विकृत मानसिकता भी कायम है कि वे भोग्य की वस्तु है? उन्हें पांव के नीचे रखा जाना चाहिए।

यों लापता होने की घटनाएं आए दिन होने वाले जघन्य अपराधों की ही अगली कड़ी है, मगर यह पुरुषवादी सोच और समाज के उस ढांचे को भी सामने करती है, जिसमें महिलाओं की सहज जिंदगी लगातार मुश्किल बनी हुई है, संकटग्रस्त एवं असुरक्षित है। भले ही महिलाओं ने अपनी जंजीरों के खिलाफ बगावत कर दी है, लेकिन देश में ऐसा वर्ग भी है जहां आज भी महिलाएं अत्याचार का शिकार होती है।

देश के अन्य हिस्सों की ही भांति गुजरात एवं मध्यप्रदेश में आदिवासी महिलाएं बड़ी संख्या में लापता हो रही है। भले एक खास महिला वर्ग ने आर्थिक मोर्चे पर आजादी हासिल की है, लेकिन एक बड़ा महिला वर्ग आज भी पुरुषप्रधान समाज की संकीर्ण एवं विकृत सोच का शिकार है। ऐसा कायम है तभी आजादी के अमृत महोत्सव मना चुके राष्ट्र की तमाम महिलाएं अपनी अस्मिता एवं अस्तित्व की सुरक्षा की गुहार लगातीं हुई दिखाई देती है। इसलिये कि उन्हें सदियों से चली आ रही मानसिकता, साजिश एवं सजा के द्वारा भीतरी सुरंगों में धकेल दिया जाता है, अत्याचार भोगने को विवश किया जाता है।

बात मणिपुर की दो महिलाओं या बंगाल के मालदा में दो महिलाओं को नग्न करने या समूचे देश में महिलाओं के लापता होने से अधिक चिन्ता की बात यह है कि इन शर्मसार करने एवं झकझोर देने वाली घटनाओं पर भी राजनीतिक दल राजनीति करने से बाज नहीं आते। इन अति संवेदनशील मुद्दों पर राजनीतिक लाभ की रोटियां सेंकना दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा हो सभी मिलकर नारी सम्मान के प्रति सचेत और संवेदनशील होकर उनके लापता होने, उन पर लगातार हो रहे अत्याचारों को रोकने की दिशा में कोई प्रभावी एवं सार्थक पहल करें। गायब होती लड़कियों और महिलाओं की बड़ी संख्या यही बताती है कि भारतीय समाज उनके प्रति अनुदार है। इस अनुदारता को दूर करने के लिए सबसे अधिक राजनीतिक वर्ग को ही आगे आना होगा और अनिवार्य रूप से समाज को भी।

नरेन्द्र मोदी की पहल पर निश्चित ही महिलाओं पर लगा दोयम दर्जा का लेबल हट रहा है। हिंसा एवं अत्याचार की घटनाओं में भी कमी आ रही है। बड़ी संख्या में छोटे शहरों और गांवों की लड़कियां पढ़-लिखकर देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वे उन क्षेत्रों में जा रही हैं, जहां उनके जाने की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। वे टैक्सी, बस, ट्रक से लेकर जेट तक चला-उड़ा रही हैं। सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा कर रही है। अपने दम पर व्यवसायी बन रही हैं।

होटलों की मालिक हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लाखों रुपये की नौकरी छोड़कर स्टार्टअप शुरू कर रही हैं। वे विदेशों में पढ़कर नौकरी नहीं, अपने गांव का सुधार करना चाहती हैं। अब सिर्फ अध्यापिका, नर्स, बैंकों की नौकरी, डॉक्टर आदि बनना ही लड़कियों के क्षेत्र नहीं रहे, वे अन्य क्षेत्रों में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। इस तरह नारी एवं बालिका शक्ति ने अपना महत्व तो दुनिया समझाया है, लेकिन नारी एवं बालिका के प्रति हो रहे अपराधों में कमी न आना, घरेलू हिंसा का बढ़ना, आदिवासी-दलित महिलाओं एवं बालिकाओं पर अत्याचारों का बढ़ना एवं उनका लापता होना, उनकी सुरक्षा खतरे में होना- ऐसे चिन्तनीय प्रश्न हैं, जिन पर सरकार को कठोर बनना होगा, सख्त व्यवस्था बनानी होगी।

सरकार ने सख्ती बरती है, लेकिन आम पुरुष की सोच को बदलने बिना नारी एवं बालिका सम्मान की बात अधूरी ही रहेगी। इस अधूरी सोच को बदलना नये भारत का संकल्प हो, इसीलिये तो इस देश के सर्वाच्च पद पर द्रौपदी मुर्मू को आसीन किया गया हैं। लेकिन उनके सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद उनके समुदाय की महिलाओं की सुरक्षा एवं अस्मिता खतरे में रहे, यह अधिक गंभीर मामला है। ■

दिल्ली में बाढ़ से उपजे विकट हालात के लिए आखिर

जिम्मेदार कौन

इस बाढ़ग्रस्त स्थिति के बीच ही देशवासियों के मन में एक सवाल निरंतर कौंध रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ की जो स्थिति बनी है, आखिरकार उसके लिए जिम्मेदार कौन है, बड़े पैमाने पर लोग इस सवाल का जवाब ढूंढ़ने में लगे हुए हैं। वैसे देखा जाये तो किसी को दोषी ठहराने से पहले स्वयं हम लोगों को भी अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना होगा जनता के द्वारा यमुना नदी की पेटी यानी कि रिवर बेड़ में बड़े पैमाने पर किया अतिक्रमण इस स्थिति को उत्पन्न करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है।

अभिषेक राय

दिल्ली में यमुना नदी के रौद्र रूप के चलते जबरदस्त बाढ़ आ गयी है, शहर की कॉलोनियों में जल भराव की गंभीर समस्या खड़ी हो गयी है। जिसके बाद से ही देश में दिल्ली की बाढ़ पर राजनेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का बहुत ही जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी के रौद्र रूप के चलते बाढ़ का आपदाकाल चल रहा है। यमुना नदी में जल ने वर्ष 1978 के रिकॉर्ड 207.49 मीटर को तोडकर 208.66 मीटर के नये रिकॉर्ड तक जलस्तर बढ़ने से देश का दिल राजधानी दिल्ली की बहुत बड़ी आबादी बाढ़ की मार को झेलने के लिए मजबूर है। आज दिल्ली की 20 फीसदी आबादी यमुना के जल के प्रकोप से किसी ना किसी रूप से त्रस्त है। दिल्ली में यमुना के आसपास के क्षेत्रों में रह रहे लोगों के सामने यमुना नदी की बाढ़ एक बड़ी चुनौती के रूप में आकर खड़ी है। दिल्ली में यमुना नदी के रौद्र रूप के चलते जबरदस्त बाढ़ आ गयी है, शहर की कॉलोनियों में जल भराव की गंभीर समस्या खड़ी हो गयी है। जिसके बाद से ही देश में दिल्ली की बाढ़ पर राजनेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का बहुत ही जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। दिल्ली की राजनीति में सक्रिय कोई भी राजनीतिक दल आपदा के इस अवसर पर अपनी सियासत चमकाने में पीछे नहीं रहना चाहता है। लेकिन हर वर्ष देश में कहीं ना कहीं बाढ़ की मार झेलने वाले आम आदमी के बीच देश में बाढ़ से बचाव के उचित प्रबंधन क्यों नहीं है, इस ज्वलंत मुद्दे के बारे में चर्चा हो रही है, लोग बाढ़ प्रबंधन को समय की मांग बता रहे हैं। वैसे भी देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में विभिन्न प्रकार की आपदाओं के कारण औसतन वार्षिक आर्थिक हानि 9.8 अरब डॉलर होने का अनुमान है, जिसमें से अकेले ही 7 अरब डॉलर से अधिक का बहुत बड़ा नुकसान तो देश में समय-समय पर आने वाली बाढ़ के कारण ही हो जाता है, जो स्थिति हम सभी के लिए बेहद चिंताजनक है और जिस पर हमें व हमारे देश के सिस्टम को समय रहते लगाम लगाने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहिए, क्योंकि भारत जैसे गरीब देश के लिए हर वर्ष इतनी बड़ी आर्थिक क्षति से मुक्ति पाना बेहद जरूरी है।

वैसे भी जब से देश में अंधाधुंध अव्यवस्थित शहरीकरण तेजी से बढ़ा है तब से शहरी क्षेत्रों में जरा सी बारिश के बाद ही बाढ़ जैसा माहौल बन जाना एक आम बात होती जा रही है। इसके चलते ही

पिछले कुछ वर्षों से जरा भी तेज बारिश के बाद ही दिल्ली के साथ देश के अन्य शहरों में बाढ़ जैसी गंभीर समस्या तत्काल उत्पन्न हो जाती है। देश में अचानक से आई बाढ़ पलक झपकते ही अपने रास्ते में आना वाले जान-माल सभी कुछ को जल प्रवाह के द्वारा लील कर अपने साथ बहाकर ले जाने के लिए तत्पर नज़र आती है। हालांकि वास्तव में बाढ़ नदी के पानी का वह अतिप्रवाह है, जिसमें आमतौर पर सूखी रहने वाली भूमि भी डूब जाती है और नदी किनारे के क्षेत्रों में बाढ़ आने पर परिस्थितियाँ अचानक से गंभीर नहीं हो जातीं, लोगों को बाढ़ से जान-माल के बचाव करने का भरपूर समय मिलता है। वैसे भी किसी भी नदी का जैसे-जैसे जलस्तर बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे ही धरातल पर बाढ़ की समस्या भी गंभीर होती जाती है, इसलिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हमेशा बरसात के समय में सजगता बरतनी बेहद आवश्यक होती है। जब से दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 208.66 मीटर तक पहुंचा है, उसके चलते दिल्ली के 6 जिलों में बाढ से हाहाकार मचा हुआ है, पूरी दुनिया दिल्ली की बाढ़ को देख रही है। हालांकि 'केन्द्रीय जल आयोग' के रिकॉर्ड के अनुसार इस वर्ष यमुनानगर के हथिनीकुंड बैराज से सबसे ज्यादा 3.59 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जबकि वर्ष 2019 और 2013 में 8 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया था, लेकिन उसके बाद भी यमुना नदी से लगे निचले इलाकों को छोड़कर बाढ़ की स्थिति इतनी खराब नहीं हुई थी, ऐसी स्थिति में सिस्टम के साथ-साथ देश के आम आदमी के लिए भी यह समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर दिल्ली में बाढ़ क्यों आई है। हालांकि राहत की बात यह रही कि केन्द्र व राज्य सरकार के द्वारा समय रहते ही राहत व बचाव कार्य तेजी के साथ किये गये हैं, जिससे बाढ़ में कोई जान हानि नहीं हुई है। सरकार के द्वारा विस्थापितों के लिए 2700 राहत कैंप बनाये गये हैं। राहत व बचाव के लिए एनडीआरएफ की 16 टीम बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में लगातार काम में लगी हुई हैं, जरूरत के अनुसार सेना भी अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से लगभग 23 हजार लोगों का रेस्क्यू किया गया है। उस सबके बावजूद भी दिल्लीवासियों के सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं, दिल्ली में पेयजल आपूर्ति करने वाले तीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गये हैं, जिससे दिल्ली को 25 फीसदी कम पेयजल मिलने के चलते पेयजल के संकट से जूझना पड़ रहा है। वहीं रिंग रोड व बाढ़ग्रस्त अन्य सड़कों को बंद करने के चलते दिल्ली में जगह-जगह भीषण ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है, पुल पर मेट्रो की रफ्तार कम कर दी गयी है। वहीं रिवर बेड में बनी झुग्गी-झोपड़ियों के साथ-साथ दिल्ली के पॉश कॉलोनी व अन्य बेहद अहम स्थल आईटीओ, राजघाट, लालकिला, सिविल लाइंस, माडल टाउन, यमुना बाजार, मोनेस्ट्री, कश्मीर गेट, आईएसबीटी, निगमबोध घाट, रिंग रोड, पुराना किला, गढ़ी मांडू आदि क्षेत्रों में बाढ़ का जल सीना तानकर अभी तक खड़ा हुआ है।

इस बाढ़ग्रस्त स्थिति के बीच ही देशवासियों के मन में एक सवाल निरंतर कौंध रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ की जो स्थिति बनी है, आखिरकार उसके लिए जिम्मेदार कौन है, बड़े पैमाने पर लोग इस सवाल का जवाब ढूंढ़ने में लगे हुए हैं। वैसे देखा जाये तो किसी को दोषी ठहराने से पहले स्वयं हम लोगों को भी अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना होगा, वैसे इस सवाल का सबसे सटीक जवाब है कि हमारे सिस्टम के द्वारा दिल्ली में यमुना नदी की तलहटी की साफ-सफाई में बरती गयी घोर लापरवाही और जनता के द्वारा यमुना नदी की पेटी यानी कि रिवर बेड़ में बड़े पैमाने पर किया अतिक्रमण इस स्थिति को उत्पन्न करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। जिसके चलते कभी लालकिले के पास बहने वाली यमुना नदी ने अपना तेजी से रास्ता बदलने का कार्य किया है, साथ ही वोटबैंक की ओछी राजनीति के चलते रिवर बेड में अतिक्रमण होने देने के चलते यमुना का जल खपाने की जगह दिल्ली में तेजी से सुकड़ती जा रही है, जिससे बहुत जल्दी ही दिल्ली में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहीं इस रिवर बेड़ की चौड़ाई कम करते हुए यमुना को पुश्ता बनाकर उसे बांधकर के बेहद संकरा कर दिया गया है, जिससे कि वह जरा सी बारिश के बाद ही बहुत ही जल्दी उफन कर अपने रौद्र रूप में नज़र आने लगती है। वहीं दिल्ली में 22 किलोमीटर लंबी बहने वाली यमुना नदी के अविरल प्रवाह को विकास के नाम पर हमने स्वयं अवरुद्ध करने का कार्य कर दिया है, वजीराबाद से ओखला तक 22 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में बने 25 पुल यमुना नदी के प्रवाह में बड़ी बाधा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे सिस्टम के चलते हर वर्ष फाइलों में साफ होने वाली यमुना नदी की तलहटी में गाद जमने से नदी की गहराई दिल्ली में हर वर्ष कम होती जा रही है, जिसके चलते जरा सी बारिश के बाद ही यमुना नदी रौद्र रूप में आकर ओवरफ्लो हो जाती है। वहीं दिल्ली में 22 किलोमीटर लंबी यमुना नदी में 22 नाले डाले जाते हैं, दिल्ली की गंदगी से भरे यह नाले यमुना को कीचड़ से युक्त करके इसके प्रवाह को अवरूद्ध करने का कार्य करते हैं, आपको बता दें कि अपनी कुल लंबाई में से मात्र 2 फीसद दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी में 80 फीसदी गंदगी दिल्ली में ही नालों के माध्यम से यमुना नदी में गिरती है, जो स्थिति बेहद चिंताजनक है। वहीं हरियाणा के यमुनानगर के हथिनी कुंड बैराज से दिल्ली तक यमुना नदी लगभग 180 किलोमीटर का सफर तय करती है, यमुना नदी की तलहटी में गाद व अतिक्रमण के चलते संकरी होने की वजह से पहले दिल्ली में हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा जाने वाला पानी लगभग चार दिन लेता था, लेकिन अब वह मात्र दो दिन में पहुंच जाता है, जिसके चलते बेहद कम समय में ही दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बन जाते है। इसलिए दिल्ली में इन सभी कारकों को जन्म देने वाले लोग यमुना नदी में बाढ़ आने के लिए जिम्मेदार हैं। ■

क्या है सर्वाइकल पेन

श्रेयांश गुप्ता

सर्वाइकल में कंधे, पीठ और गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द होता है। यह लेटने या बैठने के गलत पॉश्चर के कारण या फिर ज्यादा देर तक मोबाइल चलाने से हो सकता है। जो लोग देर तक कम्प्यूटर पर काम करते है उनमें सर्वाइकल की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। यदि आप एक ही पॉश्चर में बैठकर कम्प्यूटर पर काम करें तो आपके कंधे और गर्दन के पिछले हिस्से पर दबाव पड़ता है जिससे सर्वाइकल पेन की दिक्कत हो जाती है। सर्वाइकल एक बोन का नाम है जो गर्दन के पिछले हिस्से में होती है। देर तक मोबाइल पर बात करने से भी सर्वाइकल पेन की समस्या हो सकती है। अभी हुए एक रिसर्च के अनुसार भारतीय महिलाओं में सर्वाइकल पेन की समस्या सर्वाधिक पायी गयी है। 50 में से एक भारतीय महिला को सर्वाइकल की समस्या है। समस्या बढ़ने पर मरीज की मौत भी हो सकती है।

सर्वाइकल के लक्षण

गर्दन में दर्द या जकड़न, गर्दन अकड़ जाना इसके सामान्य लक्षण है। गर्दन और रीढ़ के जोड़ वाले हिस्से जिसे सर्वाइकल स्पाइन कहते है में समस्या होने पर सर्वाइकल की समस्या होती है।

सर्वाइकल पेन के कारण और बचाव

कम्प्यूटर पर लगातार काम

एक ही पॉश्चर में लगातार कम्प्यूटर पर काम करने से आपके कंधे और रीढ़ की बोन्स में दबाव पड़ता है जिससे सर्वाइकल की समस्या होती है। कम्प्यूटर पर काम करते समय आप बीच-बीच में ब्रेक लेते रहें। एक ही पॉश्चर में लगातार काम ना करें इससे आपको सर्वाइकल के अलावा और भी दिक्कते हो सकती हैं। काम करते समय बैठने का पॉश्चर सही होना चाहिए। सिर को एक ही दिशा में झुका कर काम ना करें इससे गर्दन और कंधे पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ेगा और आप सर्वाइकल पेन का शिकार हो सकते हैं।

ज्यादा स्ट्रेस

ज्यादा स्ट्रेस भी सर्वाइकल पेन की वजह बन सकता है इसलिए किसी भी तरह की टेंशन या ज्यादा स्ट्रेस लेने से बचें अगर कोई परेशानी है तो उसका निदान करें या मनोचिकित्सक की सलाह लें।

सोने का गलत तरीका

सोने का गलत तरीका भी आपको सर्वाइकल पेन दे सकता है। इसलिए सोने का पॉश्चर सही रखें। सोते समय आरामदायक बिस्तर का चयन करें। गलत सोने का तरीका आपकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर गलत प्रभाव डाल सकता है।

व्यायाम

रोजाना योग और व्यायाम आपको सर्वाइकल की परेशानी से छुटकारा दिलाने में मदगार हो सकते हैं। यह आपकी इम्युनिटी को भी स्ट्रांग बनाने का बेहतर ऑप्शन हैं।

बर्फ की सिकाई

अगर आपको सर्वाइकल पेन की समस्या है और आप किसी कारणवश डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहें हैं तो बर्फ की सिकाई आपको सर्वाइकल पेन से राहत देगा। डिस्क्लेमर: इस लेख के सुझाव सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन सुझावों और जानकारी को किसी डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह के तौर पर न लें। किसी भी बीमारी के लक्षणों की स्थिति में डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ■

एलोवेरा फेस पैक

मिताली जैन

जब ठंड का मौसम होता है तो स्किन को अतिरिक्त केयर की जरूरत होती है ताकि स्किन अधिक स्मूद नजर आए। इस मौसम में स्किन का ख्याल रखने के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल करना काफी अच्छा माना जाता है। दरअसल, एलोवेरा स्किन की कई तरह की प्रॉब्लम्स को नेचुरल तरीके से दूर कर सकता है। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको एलोवेरा की मदद से बनने वाले कुछ ऐसे फेस पैक के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप विंटर में आसानी से बनाकर अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं-

आवश्यक सामग्री-

- दो बड़े चम्मच एलोवेरा जेल
- एक चम्मच शहद
- एक चम्मच रोज वाटर

फेस पैक बनाने का तरीका-

- फेस पैक बनाने के लिए आप सबसे पहले एलोवेरा का पत्ता तोड़कर उसका जेल निकाल लें।
- अब आप इस जेल में शहद व रोज वाटर मिक्स करें।
- इसके बाद आप अपने फेस को क्लीन करके इस पैक को चेहरे पर लगाएं और बेहद हल्के हाथों से मसाज करें।
- करीबन 10 मिनट बाद गुनगुने पानी की मदद से फेस वॉश करें।

एलोवेरा जेल और टी ट्री ऑयल से बनाएं फेस पैक

अगर आपकी स्किन बहुत अधिक ऑयली है या फिर एक्ने प्रोन है तो ऐसे में आप इस फेस पैक को बना सकती हैं।

आवश्यक सामग्री-

- 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल
- 1 बड़ा चम्मच रोज वाटर
- 2-3 बूंद टी ट्री ऑयल

इस्तेमाल करने का तरीका-

- सबसे पहले आप एलोवेरा के पत्ते को तोड़कर उसका जेल निकाल लें।
- अब आप इस जेल में रोज वाटर और 2-3 बूंद टी ट्री ऑयल मिलाएं।
- अब आप इसे पैक को अपने चेहरे पर 15-20 मिनट के लिए लगाएं और फिर इसे धो लें।
- आप सप्ताह में एक से दो बार इस फेस पैक को लगा सकते हैं।

एलोवेरा और विटामिन ई से बनाएं फेस पैक

अगर आपकी स्किन को विंटर में डीप नरिश्मेंट देना चाहती हैं तो ऐसे में एलोवेरा जेल को विटामिन ई ऑयल कैप्सूल को मिक्स करें।

आवश्यक सामग्री-

- 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल
- एक विटामिन ई कैप्सूल

इस्तेमाल करने का तरीका-

- सबसे पहले एलोवेरा के पत्ते को तोड़कर उसका जेल निकाल लें।
- इसके बाद आप बाउल में विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल मिक्स करें।
- अब आप अपने चेहरे को वॉश करें और इस पैक को लगाएं।
- करीबन दस मिनट बाद आप अपने चेहरे को पानी की मदद से वॉश करें।

रश्मिका का क्यूट अंदाज

रश्मिका मंदाना के एक नए वीडियो पर उनके फैंस जमकर रिएक्ट कर रहे हैं, जिसे एक सेलिब्रिटी फोटोग्राफर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है. रश्मिका मंदाना जब एयरपोर्ट में एंट्री कर रही थीं, तब पैपराजी ने उनसे फोटो खिंचवाने के लिए कहा. पैपराजी को इतनी सुबह देखकर रश्मिका हैरान थीं. उन्होंने ऐसा सवाल पूछा, जिसका जवाब सुनकर एक्ट्रेस शरमाने लगीं. वीडियो में, रश्मिका कैजुअल ड्रेस में काफी प्यारी लग रही हैं. उन्होंने सफेद रंग की हाफ शर्ट और काली टीशर्ट पहनी हुई है. पैपराजी के अनुरोध पर, उन्होंने चेहरे से मास्क हटाकर कैमरे के लिए मुस्कुराते हुए खूबसूरत पोज दिए. वे अगले ही पल पैपराजी से पूछती हैं, 'क्या आप लोग सोते नहीं हैं?' वहां मौजूद सभी फोटोग्राफर्स के अलग-अलग जवाब थे, लेकिन एक फोटोग्राफर ने कहा, 'आप वाकई में बहुत सुंदर हैं.' यह बात सुनकर रश्मिका शर्म से पानी-पानी हो गईं और एयरपोर्ट में एंट्री करने से पहले फोटोग्राफर को फ्लाइंग किस दिया और हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ गईं. रश्मिका ने बताया कि वे सीधा बिस्तर से उठकर आ रही हैं. वीडियो पर, एक फैन ने कमेंट किया, 'वे नींद भी नहीं ले पा रही हैं.' दूसरे यूजर ने कहा, 'सिंपल और क्यूट लड़की.' तमाम फैंस कमेंट करके रश्मिका को अपना क्रश बताने लगे. रश्मिका को आखिरी बार 'गुडबॉय' में देखा गया था, जिसमें उन्हें अमिताभ बच्चन और नीना गुप्ता जैसे उम्दा कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला. दर्शक उन्हें बॉलीवुड के अन्य सितारों के साथ स्क्रीन साझा करते हुए देखेंगे. वे रणबीर कपूर के साथ 'एनिमल' और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ 'मिशन मजनू' में नजर आएंगी. ■

काबू पाइए मार्केट की
अस्थिरता पर
बैलेन्स्ड एड्वान्टेज फ़ंड्स के साथ.
अपने पोर्टफोलियो को दीजिए इक्विटी और डेट का शानदार मिश्रित रूप. बैलेन्स्ड एड्वान्टेज कैटेगिरी में फ़ंड्स का लक्ष्य होता है मार्केट के उतार-चढ़ाव को संभालने में आपकी मदद करते हुए अधिक से अधिक मार्केट लिंक्ड आमदनी दिलाना.
अपने निवेश में विविधता लाए
बैलेन्स्ड एड्वान्टेज फ़ंड्स के साथ
अपने एमएफडी/ आरआईए से संपर्क करें
म्यूचुअल फ़ंड्स में निवेश करने के लिए, एककालिक अपने ग्राहक को जानिए (KYC) की अपेक्षाओं को पूरा करने की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी हेतु https://www.hdfcfund.com/information/key-know-how पर विजिट करें. निवेशकों को केवल रजिस्टर्ड म्यूचुअल फ़ंड्स के साथ व्यवहार करना चाहिए, जिनके विवरण का सत्यापन सेबी की वेबसाइट (www.sebi.gov.in/intermediaries.html) पर किया जा सकता है. किसी पूछताछ, शिकायत तथा समस्या के समाधान के लिए निवेशक एएमसीज़ तथा/या निवेशक संपर्क अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. इसके साथ ही, अगर निवेशक एएमसीज़ द्वारा दिए गए समाधान से संतुष्ट न हों तो https://scores.gov.in पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. स्कोर्स पोर्टल निवेशकों को सेबी को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने तथा तत्पश्चात इसकी स्थिति को देखने की सुविधा प्रदान करता है.
निवेशक की जानकारी के लिए एक पहलकारी कदम
HDFC
MUTUAL FUND
BHAROSA APNO KA
म्यूच्युअल फ़ंड निवेश बाज़ार के जोखिमों के अधीन हैं, योजना से जुड़े सभी दस्तावेज़ों को ध्यान से पढ़ें.

कैलास जीवन

मल्टिपर्पज् आयुर्वेदिक क्रीम

। एड़ियों का फटना । मुहाँसे । हाथ पाँव और आँखों की जलन ।
। फिशर्स । कटना । जलना । आदी के लिए गुणकारी

एड़ियों का फटना

कैलास जीवन फटी एड़ियों पर लगाइए। के. जे. क्रीम त्वचा में घुलमिल जाता है। फटी एड़ियों पर असरदार होता है। पाँव की त्वचा साफ, मुलायम बनती है।

कील-मुहाँसे

कैलास जीवन हलके हाथों से चेहरे पर लगाइए (मलिए नही)। कील-मुहाँसों की तकलीफ से राहत मिलेगी। चेहरा साफ होकर निखर आएगा।

आँखों की जलन

कैलास जीवन आँखों की पलकों पर लगाइए। आँखों की जलन से आराम मिलता है और शान्त गहरी निद्रा आती है।

फिशर्स

कैलास जीवन प्रतिदिन २-३ बार 'उस' जगह पर लगाईए। और एक चम्मच **कैलास जीवन** उतनी ही मात्रा पिसी शक्कर मिला कर रोज रात २१ दिनों तक खाइए। इससे फिशर्स से राहत मिलती है।

Available in: 20g Tube, 30g, 60g, 120g, 230g Bottle

Manufacturer: **ASUM**, Pune. **020-24486865** । Customer Care: Prashant: **91300 26070** । **asumkj@gmail.com** । **www.asum.com**

Distributor: Gopal Stores, Delhi. Ph: 9810524934 | **Noida: Future Ayurveda Ph.: 8860444666** | Seelampur: **Agarwal Ayurvedic:** 9711251291, Saraswati Vihar : **Saraswati Ayu:** 27058720, Motinagar: **Luthra Dawakhana:** 9810439953, Con. Circus: **Nath:** 9899441605, Gaziabad: **Vinod Mktg:** 9971978167, Khan Market: **Preet Medicos:** 9899659582, Gurgaon: **Vashishth Medical:** 9873321179, Noida: **Ajay Medical:** 0120-2527981, Faridabad: **Laxmi Ayurvedic:** 9810083760, Also Available at **Chandni Chowk, Bhagirath Palace, Khari Baoli.**

Also available on **amazon** | netmeds.com